



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2003/अग्रहायण 20, 1925

No. 293]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2003/AGRAHAYANA 20, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2003

प्रारम्भिक जांच परिणाम

**विषय:** चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, ताईवान तथा ब्राजील से 3000 से 4000 आणविक भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोल के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच

सं० 14/4/2003-डीजीएडी- भारत सरकार वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:-

- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत मै० मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि० मनाली, चेन्नई जो घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है, से एक लिखित याचिका प्राप्त की थी जिसमें चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, ताईवान तथा ब्राजील (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 3000 से 4000 आणविक भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोल (जिसे इसमें इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है।

- (ii) आवेदन की प्रारंभिक जांच में कतिपय त्रुटियों का पता चला जिसे बाद में याचिकाकर्ता द्वारा दूर कर दिया गया। इसलिए इस याचिका को बाद में उचित रूप से दस्तावेज युक्त माना गया।
- (iii) प्राधिकारी ने उक्त नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरुआत की कार्यवाही से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को कथित घाटन के संबंध में प्राप्त याचिका के बारे में सूचित किया।
- (iv) प्राधिकारी ने दिनांक 21 मई, 2003 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष 3907.20, 3907.99 और 3907.91 के अंतर्गत शामिल 3000 से 4000 तक आणविक भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोले के आयात के संबंध में पाटनरोधी कार्यवाही शुरू की गयी है।
- (v) प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों, आयातकों एवं शिकायतकर्ताओं को उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति अग्रेषित की और उन्हें लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का एक अवसर प्रदान किया।
- (vi) उपर्युक्त नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों एवं भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को याचिका की एक प्रति प्रदान की।
- (vii) प्राधिकारी ने निम्नलिखित निर्यातकों को संगत सूचना मांगने के लिए प्रश्नावलियों भेजी:-

मैसर्स एस.के. ओक्सिकैमिकल कं० लि०,  
23-10 योइडो डोंग  
योंगडुंगपो-जीयू, सिओल,  
दक्षिण कोरिया-180-0101

मै० बायेर पोलि यूरेथानेस ताईवान लि०,  
2एफ290 चुंग हेसियाओ ई रोड, से.4,

ताईपेई, ताईवान

झियांग सानहुयान कैमिकल क० लि०  
सं० 1007 जियू लियांगक्सी रोड,  
योंगकांग  
झियांग 32130, चीन जन.गण

डोव क्यूमिका एस.ए.  
रूआ एलेक्जेंडर डुमास  
167, पी.पी. बॉक्स 9037  
010065-970 साओ पोलो  
ब्राजील

(viii) नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को जांच की शुरुआत के बारे में सूचना दी गई और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का जवाब निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें।

(ix) निम्नलिखित आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई:-

1. मै० फीदर फोम एन्टरप्राइजेज प्रा० लि०  
प्लॉट नं० 257, सैली  
उमर्कवी रोड  
सिल्वासा-396230(दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र)
2. मैसर्स नाटसन फोम मैन्यू. प्रा० लि०,  
5, पंचायत भवन, भद्रास,  
अहमदाबाद-1
3. मैसर्स डुरा फोम इंडस्ट्रीज प्रा० लि०  
123, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, सिल्वासा  
दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र

4. मैसर्स सूर्या फोम,  
सेदारपेट मेन रोड  
सेदारपेट, पांडिचेरी
5. मैसर्स डीपी फोम प्रा० लि०,  
13, रंगपिल्लाई स्ट्रीट,  
पी.बा सं० 130,  
पांडिचेरी-605001.
6. मैसर्स कुर्ल ऑन लि०,  
जलाहल्ली कैम्प रोड,  
यशवंतपुर,  
बंगलौर-560022.
7. मैसर्स अपर्णा पॉलिप्रोडक्ट्स लि०,  
452, गणपति प्लाजा  
एम.आई. रोड,  
जयपुर-302001 (राजस्थान)
8. मैसर्स तिरुपति फोम्स लि०,  
502, हरेकृष्णा कॉम्प्लेक्स  
कोठवाला फ्लेट्स के सामने  
प्रीतम नगर, एलिस ब्रीज  
अहमदाबाद-380006
9. मैसर्स सॉफ्ट फोम इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०,  
सर्वे सं० 3852, मेडचल इण्डस्ट्रियल एरिया  
आर.आर. जिला-501401 (आ.प्र.)
10. मैसर्स मद्रास पॉलिमाउण्डस  
28, सी एंड कृष्णास्वामी एवेन्यू  
मेलापुर  
चेन्नई

11. मैसर्स शीला फोम प्रा० लि०,  
37/2, साइड नं० iv, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,  
साहिबाबाद-201010  
गाजियाबाद (उ० प्र०)
12. मैसर्स जे.जे. फोम्स प्रा० लि०  
बी-12/2, साइट- iv, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,  
साहिबाबाद(जिला गाजियाबाद)उ.प्र.
13. मैसर्स एम.एच पालिमर्स प्रा० लि०,  
बी-15, साईट बी, सूरजपुर इंड. एरिया  
तहसील, दादरी  
जिला गाजियाबाद(उ.प्र.)
14. संदीप फोम इण्डस्ट्री प्रा० लि०,  
यूनिट- II, बी-374 मेन रोड  
गाजीपुर गांव  
दिल्ली-110096
15. अरविन्द इण्टरनेशनल लि०,  
ई-95-96 एवं 76-78 रिको इंडस्ट्रियल एरिया  
बागरू एक्सटेंशन  
बागरू-303007  
राजस्थान
16. दुरा पफ(सिल्वासा)प्रा० लि०,  
121, पिपरिया औद्योगिक एस्टेट  
दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र  
वाया वापी (प० रेलवे), सिल्वासा
17. जॉय फोम प्रा० लि०,  
55-बी/3 सिप्को औद्योगिक एस्टेट  
रानीपेट

18. देवी फोम प्रा० लि०  
391-ए, गांडे ताल, इगतपुर,  
नासिक-मुंबई रोड,  
नासिक, महाराष्ट्र
19. स्विस फोम इंडस्ट्रीज  
823 एवं 825, जी आई डी सी फेस-II,  
चत्तराल, कालोज,  
गुजरात
20. कोजी फोम्स प्रा० लि०,  
प्लॉट नं० 17, सर्वे नं० 820/एफ,  
ग्राम - महिम, (चिंट्जपडरा)  
पालघर, जिला-थाणे
21. फोम होम (इंडिया) प्रा० लि०  
एच-30/2/एमआईडीसी ताजोजा  
महाराष्ट्र
22. रामेणा फोम प्रा० लि०,  
36 कैनाल रोड,  
कुदपक्कम,  
विलानपुर  
पांडिचेरी-605110
23. अल्फा कैमिकल कारपोरेशन  
गोडाउन नं० 19  
शिव कम्पाउण्ड,  
रहनाल गाँव,  
भिवंडी 421302  
जिला - थाणे
24. पॉलियूरेथाने एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

मि. के. राममूर्ति,  
सचिव  
फ्लैट 7, तीसरा तल, शक्तिमहल,  
न्यू नं० 24(ओल्ड 41), फर्स्ट मेन रोड,  
सिट कालोनी, मीलापुर,  
चेन्नई-600004.

- (x) याचिकाकर्ताओं से क्षति के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी गयी थी जो प्रस्तुत की गयी थी :
- (xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में इच्छुक पक्षकारों द्वारा जांच के लिए खुला रखा ।
- (xii) कुछेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था जिसकी मंजूरी प्रदर्शित उचित कारण के आधार दे दी गयी थी ।
- (xiii) इस अधिसूचना में \*\*\* चिह्न से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के अंतर्गत इसे प्राधिकारी ने गोपनीय ही माना है ।
- (xiv) जांच में 1 अप्रैल, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक की अवधि शामिल है ।
- (xv) जांच आरंभ करने संबंधी सूचना की प्रतियां भी फिक्की, सीआईआई, एसोचेम • इत्यादि को व्यापक परिचालन हेतु भेजी गई थीं ।

### ख. याचिकाकर्ता के विचार

3. याचिकाकर्ता ने अपने अनुरोधों में निम्नलिखित प्रमुख तर्क दिए हैं:-
- (i) याचिका चीन, कोरिया, ब्राजील और ताईवान (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश/देशों कहा गया है) मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध उत्पादों के विरुद्ध दायर की गयी है ।

- (ii) एमपीएल भारत में प्रॉप्लीन आक्साइड का एकमात्र उत्पादक है जो मूल कच्ची सामग्री के रूप में प्रॉप्लीन का शुरू से प्रयोग करता है और जिसे फ्लेक्सिबिल पॉलियॉल का निर्माण करने के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है।
- (iii) इस उत्पाद का उपयोग फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक फोम के उत्पादन में किया जाता है। इस उत्पाद का कोई प्रतिस्थापन नहीं है।
- (iv) 3000-4000 आणविक भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियॉल का उपयोग स्लैबस्टॉक फोम के विनिर्माण में किया जाता है। उन वस्तुओं जिनके उत्पाद रेंज का उत्पादन करने की याचिकाकर्ता क्षमता रखता है, के ब्यौरों में प्रॉप्लीन आक्साइड, प्रॉप्लीन ग्लिकोल और पॉलीडर पॉलियोल के विभिन्न ग्रेड (फ्लेक्सिबल, रिजिड एवं ऐलास्टोमर, विशिष्ट ग्रेड) शामिल हैं। याचिकाकर्ता के पास व्यापार करने के लिए अपने उत्पाद के समान अन्य किसी माल का आयात नहीं करता है।
- (v) याचिकाकर्ता द्वारा भारत में विनिर्मित संबद्ध माल आयातित माल का वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है। इसलिए 'समान वस्तु' की सभी शर्तें पूरी करता है।

#### 4. पाटन के बारे में

- (i) हमने कोरिया, ताईवान और ब्राजील के घरेलू बाजार में संबद्ध माल की कीमतों के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमने निर्यातकों की कीमत सूची अथवा अन्य देशों को उनकी निर्यात कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए थे। हम संबद्ध देशों में संबद्ध माल की कीमतों के बारे में न तो उस देश में बिक्री के लिए अथवा अन्य देशों को निर्यात के लिए निर्यातकों की कीमत सूची के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं रहे हैं। संबद्ध देशों में सामान्य परिकलित मूल्य की दृष्टि से यह संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का उत्तम सूचक है विशेषतौर पर जब कीमतें कच्ची सामग्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
- (ii) चीन के मामले में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के प्रावधान लागू हैं क्योंकि भारत सहित डब्ल्यू टी ओ के कई सदस्यों ने चीन को पिछले



तीन वर्षों में गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना है। तदनुसार माननीय प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 7 और 8 में यथानिर्धारित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करें।

- (iii) हम तीसरे देशों में कीमतें मालूम नहीं कर सके हैं जिससे उपयुक्त पैराओं में दिए गए कारणों से चीन में उपलब्ध कीमतों को उचित रूप से निर्धारण किया जा सके। जैसाकि नियमों में प्रावधान है विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया जांच प्रारंभ के प्रयोजनार्थ भारत में देय कीमतों के आधार पर कीमतें स्वीकार करें।
- (iv) सम्बद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का परिकलन इस आवेदन के भाग 1 में यथा उल्लिखित आयात आंकड़ों के सी आई एफ मूल्यों के साथ-साथ हमारे पास उपलब्ध उन आंकड़ों के आधार पर किया गया है। सम्बद्ध देश भारत में संबद्ध उत्पादों का निर्यात उन कीमतों पर कर रहे हैं जो उनके सामान्य मूल्यों से बहुत ही कम हैं।

## 5. क्षति के संबंध में

### i) संचयी मूल्यांकन

प्रत्येक सम्बद्ध देश से पाटन मार्जिन 2 प्रतिशत सीमा से अधिक है जिन्हें निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा भी न्यूनतम से अधिक है। आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित होगा क्योंकि सम्बद्ध देशों से आयातों की एक-दूसरे के साथ और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा है इसलिए प्राधिकारी से सम्बद्ध देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी रूप से मूल्यांकन करने का अनुरोध है।

### ii) सम्बद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा

सम्बद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा सकल आयातों के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2001-2002 में 1.48% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 98.57% हो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि आयातक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हुए लगातार पाटित कीमतों पर आयात कर रहे हैं।

सकल मांग में सम्बद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा 2001-2002 के दौरान 0.59% से तेजी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 32.90% हो गया है ।

iii) भारतीय उत्पादों द्वारा धारित बाजार हिस्से में परिवर्तन

घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा 2000-2001 में 87.25% से कम होकर जांच अवधि के दौरान 66.45% रह गया है । तथापि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कुछ वृद्धि हुई है क्योंकि यह पाटित सामान की कीमतों के साथ समानता करने के लिए बहुत ही कम कीमतों पर बिक्री कर रहा है । यह वृद्धि प्राथमिक रूप से अन्य देशों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण देश में घरेलू उद्योग को क्षति आरंभ होने से पूर्व घरेलू उद्योग को एक बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त थी ।

iv) निर्गत, उत्पादकता तथा क्षमता उपयोग

जांच की अवधि में उत्पादन के साथ-साथ घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है । यह प्रमुखतः इस तथ्य के कारण हुआ कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 21 सितंबर, 2001 को चार प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध जांच का आरंभ किया था तथा इसके परिणामस्वरूप अधिसूचना सं० 17/2002-सीमाशुल्क के अनुसार 11 फरवरी 2002 को अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे । भारत सरकार द्वारा की गई इस उपचारात्मक कार्रवाई से घरेलू उद्योग अपने उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में सुधार करने में समर्थ हो सका, जो कि सम्बद्ध देशों से पाटन के कारण पुनः खतरे में है ।

v) बिक्री मात्रा तथा मूल्य

पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है । तथापि, यह देखा जाना है कि घरेलू उद्योग केवल कीमतों में कटौती द्वारा ही अपनी बिक्री में वृद्धि करने में समर्थ हुआ है जिसके परिणामस्वरूप बिक्री मात्रा में सुधार के बावजूद घाटा हुआ है । क्षमता उपयोग में सुधारा करने के पश्चात् याचिकाकर्ता ने उत्पादन को कम कीमतों पर भी बेचने

का विशेष प्रयास किया है ताकि उसे बढ़ी हुई वस्तु सूचियों का भार न उठाना पड़े ।

#### vi) आयात कीमत विश्लेषण

जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात कीमत में काफी गिरावट हुई है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-02 में संबद्ध देशों से कीमतों में आंशिक वृद्धि हुई है परंतु 2000-01 में 43402 रूपए से जांच अवधि के दौरान 41852 रूपए की तीक्ष्ण गिरावट हुई है । कीमतों में गिरावट को जांच की अवधि के दौरान इन स्रोतों से आयातों में भारी वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए (2000-2001 में केवल 48 मी. टन से जांच अवधि के दौरान 4550 रू० (वार्षिक) तक) ।

#### vii) वस्तु सूचियाँ

याचिकाकर्ता अलाभकारी कीमतों पर उत्पादन स्टॉकों की बिक्री द्वारा ही अपनी वस्तु सूचियों में कटौती करने में समर्थ हुआ है ।

वर्ष 1		वर्ष 2		जांच की अवधि (9 महीने)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
मी. टन	लाख रूपए	मी. टन	लाख रूपए	मी. टन	लाख रूपए
100	100	130.33	126.44	26.84	23.82

#### viii) कीमत कटौती

संबद्ध देशों से पाटित आयातों में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है । कटौती की सीमा चीन में 11.64%, कोरिया में 7.90%, ताईवान में 13.92% तथा ब्राजील में 22.46% है । यह देखा जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग की वर्तमान कीमतों, जिनके कारण हानि हो रही है, में भी संबद्ध देशों से आयातों के द्वारा कटौती हो रही है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति हो रही है ।

**ix) लाभप्रदता तथा निवेश पर आय**

घरेलू उद्योग को प्रत्यक्ष घाटे के रूप में प्रति इकाई बिक्री पर गंभीर क्षति हो रही है। विवेचनीय है कि मात्रा प्रभाव के साथ-साथ यह कीमत कारक घरेलू उद्योग को हो रही व्यापक क्षति का कारण है। उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री के यथोचित अच्छे स्तर के बावजूद, हो रहा निरंतर घाटा घरेलू उद्योग के हितों के लिए अत्यधिक क्षतिकारी है। पूंजी एकत्र करने तथा आगे विस्तार हेतु निधि जुटाने की हमारी क्षमता पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा है।

**x) गंवाई गई संविदाओं के प्रमाण**

गंवाई गई संविदाओं के प्रमाण गोपनीय अनुबंध के रूप में संलग्न हैं।

**xi) रोजगार तथा वेतन**

मानवशक्ति में 2000-2001 में 576 से जांच अवधि के दौरान 430 की अत्यधिक गिरावट हुई है। घरेलू उद्योग पर पाटन का इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि पिछले कुछ वर्षों में वह वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति प्रदान करने में असमर्थ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि उद्योग (विवाद तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 12(3) के तहत मजदूर यूनियन के साथ नए वेतनमान के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, जो कि प्रबंधन के समक्ष अनेक आवेदनों के पश्चात् भी जनवरी, 2001 से लंबित है।

**xii) नकद प्रवाहों पर वास्तविक तथा संभावित नकारात्मक प्रभाव**

चूंकि फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पालियॉल को जांच अवधि के दौरान नकद घाटा हुआ है, इससे समग्र रूप में कंपनी की नकद प्रवाह स्थिति पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।

**xiii) पूंजी जुटाने की क्षमता अथवा निवेश एवं वृद्धि**

वित्तीय घाटों की वर्तमान स्थिति के साथ घरेलू उद्योग का इस व्यवसाय में और आगे निवेश करना व्यवहार्य नहीं होगा।

#### xiv) पाटन मार्जिन की मात्रा

याचिकाकर्त्ताओं ने परिकलित लागत पद्धति के आधार पर चीन के लिए 106.83%, कोरिया के लिए 93.44%, ताईवान के लिए 113.38% तथा ब्राजील के लिए 135.25% के पाटन मार्जिन का अनुमान लगाया है। ब्यौरे याचिका में उपलब्ध हैं।

#### 6. कारणात्मक संबंध

- (i) चीन, कोरिया, ताईवान तथा ब्राजील के अलावा किन्हीं अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात न्यूनतम से कम हैं तथा जांच अवधि के दौरान उच्च कीमतों पर उपलब्ध हैं। केवल चीन, कोरिया, ताईवान तथा ब्राजील से पाटित कीमतों पर आयात हो रहे हैं जिससे याचिकाकर्त्ताओं को वास्तविक क्षति हो रही है।
- (ii) संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि प्रदर्शित हो रही है। इसलिए, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता। यह भी देखा जाना चाहिए कि बाजार आकार में वृद्धि हो रही है अतः घटती मांग घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।
- (iii) संबद्ध वस्तुओं के लिए केवल एक बाजार है जहां पाटित आयात, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। कीमतों के आधार पर आपूर्तिकर्त्ता की रूचि का निर्धारण किया जाता है। स्थानीय उत्पादकों के लिए पाटित आयात समान वस्तु के अच्छे विकल्प माने जाते हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादित फ्लेक्सिबल पॉलियॉल के समान वाणिज्यिक ग्रेड तथा मानक विशिष्टि प्राप्त करने के लिए आयातित उत्पादों की बिक्री की जाती है। आयातित संबद्ध वस्तु तथा घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तु समान वस्तु हैं तथा समान अनुप्रयोगों/उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। अतः आयात स्रोतों अथवा घरेलू स्रोतों से वस्तु की खरीद में कीमत सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। घरेलू उद्योग का हिस्सा, पाटित आयातों के न होने की स्थिति में और बेहतर होता। संबद्ध उत्पादों की बिक्री में घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है। संबद्ध देशों से कम कीमतों पर आयात को इसका सीधा कारण माना जा रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों से आयातकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों की बराबरी करने की अपेक्षा की जाती है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों की गैर-मौजूदगी में घरेलू उद्योग समुचित लाभ मार्जिन के साथ अपनी उचित बिक्री कीमत प्राप्त करने में सफल हो गया होता।

१. निर्यातकों, आयातकों, उपयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

७. निम्नलिखित निर्यातकों से उत्तर प्राप्त किए जा चुके हैं:-

- (i) मै0 एस के सी कं0 लि0, कोरिया
- (ii) मै0 डाओ क्विमिका एस.एस. ब्राजील
- (iii) मै0 जिन हुआ केमिकल्स (ग्रुप) कार्पोरेशन, चीन
- (iv) मै0 बेयर पॉलियूरेथेन्स, ताइवान

८. केवल मै0 एस के सी कं0 लि0, कोरिया ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है ।

९ मै0 डाओक्विमिका एस.ए. ब्राजील ने प्राधिकारी द्वारा समान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के लिए प्रश्नावली में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । तथापि, उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां की है :-

- (i) प्राधिकारी ने उत्तर दायर करने लिए समय सीमा में दो हफ्ते का विस्तार किया था किंतु उपलब्ध समय, अपेक्षित वृहदाकार गोपनीय आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कम था ।
- (ii) आवेदक - एम पी एल, भारत में फ्लेक्सिवल स्लैबस्टॉक पॉलियॉल (एफ एस पी) के एकमात्र उत्पादक हैं । यू एस ए, जापान, सिंगापुर तथा ईयू से समान उत्पादों के निर्यातों पर पिछले वर्ष ही पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । एकमात्र उत्पादक होने के कारण याचिकाकर्ता की मंशा एकाधिकार प्राप्त करने की प्रतीत होती है, जिससे कि वे उपयोक्ताओं पर अपनी शर्तें लागू कर सकें ।
- (iii) बाजार मांग 17,500 मी. टन की है जिसमें 12 से 15% प्रति वर्ष की दर पर वृद्धि हो रही है । याचिकाकर्ता के पास इस मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है । याचिकाकर्ता अलग-अलग अनुप्रयोगों के लिए अलग-अलग ग्रेडों के पॉलियॉल का निर्माण करते हैं । बकाया मांगों की पूर्ति आयातों द्वारा की जानी चाहिए ।
- (iv) याचिकाकर्ताओं की उत्पादन सुविधाएं अत्यधिक खर्चीली होना ही उनकी समस्याओं का कारण है । तथ्यतः कुल आयातों की मात्रा 2001-02 में 4553.27 मी. टन से जांच की अवधि में 3461.69 तक घट गई है ।

जहां तक ब्राजील से होने वाले आयातों का संबंध है, आयातों में वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि जांच अवधि सू पूर्व ब्राजील से कोई आयात नहीं हुए थे ।

- (v) पूर्ववर्ती मामले की याचिका के साथ तुलना किए जाने पर याचिकाकर्ताओं का 2000-01 में 87.25% का बाजार हिस्सा रखने का दावा सही प्रतीत नहीं होता है । आगे, 87.25% जैसे ऊंचे बाजार हिस्से के साथ, उत्पाद के आयातों का उन पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।
- (vi) जांच की अवधि के लिए भारत में आयात के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार औसत सी एफ आर 783.4 अम0 डा0 प्रति मी. टन है । उनके द्वारा की गई आपूर्तियां बल्क में हुई हैं, जिसके कारण ड्रम पैकिंग तथा संबद्ध लागतों में बचत हुई है ।
- (vii) याचिकाकर्ता का दावा कि आयातों का होना कीमत में कटौती का सीधा कारण है, सत्य नहीं है । यह 2000-01 से आयात शुल्कों में हो रही कटौती से संबंधित हो सकता है ।
- (viii) उनकी वार्षिक रिपोर्ट में घोषित क्षमता आंकड़े तथा उनकी पूर्ववर्ती याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बाजार हिस्से संबंधी आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अपने एफ एस पी क्षमता/उपयोग के संबंध में याचिकाकर्ता की जानकारी भ्रांतिपूर्ण है । यह याचिका त्रुटिपूर्ण आंकड़ों पर आधारित है तथा इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए ।
- (ix) याचिकाकर्ता की लाभप्रदता तथा निवेश पर आय केवल एक उत्पाद (हेटरो पॉलियॉल) पर आधारित नहीं हो सकती है, जिसका उसके कुल राजस्व में केवल 27% हिस्सा है । याचिकाकर्ता की परेशानियों का कारण, एफ एस पी की कीमत नहीं बल्कि समग्र रूप से अक्षम उत्पादन प्रक्रिया, संयंत्र आकार तथा कच्ची सामग्री तथा अन्य उपयोगिताओं की उपलब्धता में अमितव्ययिता है ।
- (x) संबद्ध देशों से आयात केवल जांच अवधि में हुए हैं, इस स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में उठाये गये नुकसान का कारण संबद्ध देशों से आयातों को नहीं माना जा सकता ।
- (xi) याचिकाकर्ता ने रक्षोपाय शुल्क अथवा पिछले वर्ष लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का इस्तेमाल अपनी औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता अथवा अक्षमताओं को सुधारने के लिए नहीं किया है ।

(xii) किसी भी पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने से केवल एक अप्रतिस्पर्धात्मक तथा एक अक्षम एकमात्र घरेलू उत्पादक का बचाव ही होगा ।

10. मै0 बेयर पॉलियूरेथेन, ताईवान ने प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु प्रश्नावली में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । तथापि, उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

- (i) हम, बेयर के रूप में अपने सबसे विश्वसनीय तकनीकी सहायता के साथ पिछले 25 वर्षों से अपने पंजीकृत ब्रांडों अरकोल 5613/डेसमोफेन 7186 के साथ आपके देश में उक्त उत्पाद के नियमित आपूर्तिकर्ता हैं ।
- (ii) हमारे उत्पाद विख्यात तथा स्थापित प्रौद्योगिकी पर आधारित है तथा भारतीय मार्केट में उनकी मांग बनी हुई है और उन्हें भारतीय बाजार में स्लैबस्टॉक फोम मार्किट में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है । उपभोक्ता हमारे उच्चकोटि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता उत्पाद तथा सेवाओं के लिए प्रीमियम अदा करना अधिक पसंद करते हैं ।
- (iii) याचिका के संबंध में हम आश्चर्यचकित एवं स्तंभित हैं क्योंकि हमारा अभिप्राय कभी भी भारतीय स्लैबस्टॉक पॉलियॉल बाजार को क्षति पहुंचाने का नहीं था और वास्तव में, हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमने ऐसा कभी नहीं किया है ।
- (iv) विश्वसनीय बाजार आसूचना के अनुसार, वर्तमान भारतीय फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियॉल बाजार आकार लगभग 18,000 मी. प्रति वर्ष है, जो पिछले तीन वर्षों से लगभग 11-12% की दुगुनी आंकड़ा वृद्धि दर से बढ़ रहा है । घरेलू उत्पादन क्षमता, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः उस कमी को आयातों के द्वारा पूरा किया जाना है ।
- (v) घरेलू उत्पादक, मै0 मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि0 लगातार सुरक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करता रहा है । उनके प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता कुशल उत्पादन प्रक्रिया तथा एक अपेक्षाकृत बड़ी आर्थिक उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है । परंतु दुर्भाग्यवश वे रक्षोपाय तथा हाल ही में यू एस, ईयू, सिंगापुर तथा जापान से हो रहे पाटन पर लगाए गए शुल्क उनके पक्ष में होने के बावजूद वे



पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दोनों में से एक भी प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

- (vi) इसके अतिरिक्त, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारतीय बाजार को पहले से ही उच्चतम संरक्षण शुल्क प्राप्त है, 25% के आधार पर सीमाशुल्क जो अन्य शुल्कों को जोड़ने के पश्चात् 33% से ऊपर चला जाता है। जबकि, भारत में एफ एस पी की प्रति व्यक्ति खपत चीन तथा अन्य विकासशील देशों की तुलना में 1/20 है जो क्षेत्र में सबसे कम है। अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान किए जाने से उपभोक्ता के लिए कीमत में वृद्धि होगी तथा इस क्षेत्र के बाजार की खपत वृद्धि/औद्योगिक वृद्धि में बाधा आएगी।
- (vii) मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि० तथा स्पिक आर्गेनिक्स का आपस में विलियन कर एक कंपनी बना दिया गया है, तथा वह अब एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। बाजार में हमारी उपस्थिति एकाधिकारिक व्यवहार को नियंत्रित करती है तथा उचित कीमतीकरण को प्रोत्साहित कर उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करती है। इस स्थिति में सुरक्षा शुल्क लगाने के किसी भी निर्णय से एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के उल्लंघन की आशंका हो सकती है जो एकमात्र स्थानीय उत्पादक को एकाधिकारिक व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करने के तुल्य होगा।

निर्यातक ने संगत आंकड़ों सहित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा में विस्तार की मांग की है। प्राधिकारी द्वारा विस्तार प्रदान किया गया था, तथापि किसी भी प्रकार का विस्तृत उत्तर अथवा प्रश्नावली प्राप्त नहीं हुई।

11. मे० जिन हुआ केमिकल्स (ग्रुप) कॉर्पोरेशन, चीन ने प्रश्नावली में अपेक्षित, पूर्ण उत्तर उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं :

- i) एजेंसी करार
- ii) घरेलू बिक्री से संबंधित बीजक(चीनी भाषा में)
- iii) उत्पाद हैंड बुक
- iv) कंपनी का परिचय
- v) भारतीय बाजार में बिक्री कीमत के संबंध में एक विवरण

12. प्राधिकारी पाते हैं कि चीन, ब्राजील तथा ताईवान के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर अत्यंत त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इनमें प्रश्नावली में अपेक्षित जानकारी नहीं दी गई है।

### आयातकों/उपयोक्ता एसोसिएशनों के उत्तर:

13. मै0 शीला फोम प्रा0 लि0 गाजियाबाद - इन्होंने आयातक प्रश्नावली के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।

14. मै0 जॉय फोम प्रा0 लि0 गाजियाबाद - इन्होंने आयातक प्रश्नावली के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है तथा निम्नलिखित तर्क भी दिए हैं:

- (i) मनाली पेट्रोकेमिकल्स एक पुराना तथा आकर में अलाभकारी संयंत्र है तथा छोटे उत्पादकों द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता से इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं बनाया जा सकता है।
- (ii) मनाली पेट्रोकेमिकल की आर्थिक समस्याएं प्रमुखतः कंपनी के कुप्रबंधन के कारण उत्पन्न हो रही हैं जैसाकि कंपनी के पूर्ववृत्त से सत्यापित किया जा सकता है।
- (iii) मनाली पेट्रोकेमिकल्स, स्पिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की संपत्ति है, जो अखबार की रिपोर्टों के अनुसार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही है तथा उनके लिए पुर्नसंरचना का प्रस्ताव किया जा रहा है।
- (iv) वर्तमान परिस्थितियों में यह विचारणीय है कि क्या पाटनरोधी शुल्क जैसे अस्थाई उपायों से कंपनी को बचाया जा सकता है।
- (v) यह हमारा अनुभव रहा है कि कंपनी विभेदकारक बिक्री नीति अपनाती रही है। इस उत्पादक का एक ऐसे बाजार में यह एकाधिकारक स्वभाव, जहां किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, यहां तक कि विकासशील देश के आयातकों की ओर से भी नहीं है, छोटे विनिर्माताओं तथा उनके कर्मचारियों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी।
- (vi) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पॉलियॉल की कीमत समयानुसार परिवर्तनों के आधार पर 900 अम0 डा0 से 1050 अम0 डा0 प्रति टन के अर्ध घटती-बढ़ती रही है। इस तथ्य के बावजूद भी कि पाटनरोधी शुल्कों के कारण सभी विकासशील देशों में उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार लगभग बंद हो गए, हमारे लिए खुले सीमित बाजार में भी कीमतों में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ यह मान लेना उचित प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी सभी विकासशील देशों में आधारभूत कीमत समान हैं। यह इस बात का संकेत है कि मौजूदा कीमतें, वाणिज्यिक नियमों पर आधारित हैं तथा वे उचित तथा तर्कसंगत हैं।

15. मै0 स्टार फोम प्रा0 लि0, चेन्नई- इन्होंने केवल निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

- i) मनाली पेट्रोकेमिकल्स संपूर्ण भारत की विपणन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है।
- ii) पॉलियॉल की कीमत आयातित पॉलियॉल से अधिक है।

- (iii) उत्पाद की गुणवत्ता, आयातित उत्पाद की गुणवत्ता के समान नहीं है ।
- (iv) मनाली पेट्रोकेमिकल ऋण / साख पत्र प्रदान नहीं करेगा
- (v) हमने 90 दिवसीय साख पत्र के विरुद्ध सामग्री आयात की है ।

16. पालीयूरेथीन एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, गाज़ियाबाद - उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं :

- (i) मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स भारत में लचीले स्लेबस्टॉक पालीओल का एकमात्र विनिर्माता है तथा वे पाटनरोधी तथा अन्य संबद्ध शुल्कों द्वारा बार-बार सुरक्षा मांगने के आदी हैं । उन्होंने रक्षोपाय शुल्क के अधीन 1998 में तथा इसके बाद पाटनरोधी शुल्क के अधीन दिसंबर 2001 में संरक्षण मांगा था ।
- (ii) याचिकाकर्ता विश्व में समस्त पालीओल विनिर्माता कंपनियों से हो रहे आयातों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ।
- (iii) याचिकाकर्ता निकृष्ट तथा पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं जो कि व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तथा प्रतिस्पर्धी नहीं हैं । वे प्रतिस्पर्धा से बचना चाहते हैं तथा देश में पालीओल की पूर्ति पर एकाधिकार करना चाहते हैं ।
- (iv) पी यू फोमिंग उद्योग की निर्यातक अथवा याचिकाकर्ता के पास पालीओल की लागत संबंधी सूचनाओं तक कोई पहुंच नहीं है ।
- (v) पालीओल पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैण्ड, मलेशिया से बहुत कम कीमत पर पीयू फोम का आयात होने लगेगा क्योंकि इन देशों में सीमाशुल्क बहुत कम है: -
- (vi) पीयू फोम उद्योग में 120 लघु इकाईयां हैं जो कि प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत कम पूंजी पर कार्य करती हैं । उद्योग पहले से ही अन्य उत्पादों यथा नारियल जूट आदि से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा है तथा पीयू फोम उद्योग पाटनरोधी शुल्क का आरोपण सहन नहीं कर सकता ।

उपर्युक्त कारणों को देखते हुए जनहित में पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए

### घ. प्राधिकारी द्वारा जांच तथा इसके परिणाम

- 17 याचिकाकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां तक प्राधिकारी के समक्षा प्रस्तुत किए गए हैं उन पर इस परिणाम तक पहुंचने के पहले जांच तथा विचार किया जा रहा है तथा जहां कहीं भी उचित होगा आगे भी विचार किया जाएगा ।
- 18 नए निर्यातकों के मामले अथवा वे मामले जिनमें कीमत संबंधी वचनबद्धता देने की इच्छा का उल्लेख है उनपर, अनुरोध किए जाने पर, नियमावली के नियमों के अनुसार, विचार किया जाएगा ।

### विचाराधीन उत्पाद

- 19 इस जांच में विचाराधीन उत्पाद 3000 से 4000 आण्विक भार का लचीला स्लेबस्टॉक पालीओल है (जिसे बाद में संबद्ध वस्तु कहा गया है) । उत्पाद का उपयोग लचीले स्लेबस्टॉक फोम के उत्पादन में किया जाता है । उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के सीमाशुल्क शीर्ष 3907.20 के अधीन कवर किया जाता है तथा अध्याय शीर्ष 3907.99 तथा 3907.91 के अधीन भी स्पष्ट किया गया है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक हैं तथा इस जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं है । विचाराधीन उत्पाद संबंधी कोई भी तर्क नहीं दिया गया है ।

### समान वस्तु

- 20 याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच कोई अंतर नहीं है । उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा भारत में विनिर्मित संबद्ध उत्पाद व्यावसायिक तथा तकनीकी रूप से आयातित उत्पाद से प्रतिस्थापन लायक है और इसीलिए समान वस्तु संबंधी सभी शर्तें संतुष्ट होती हैं । इस दावे के विरोध में कोई तर्क नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 3000 से 4000 आण्विक भार के लचीले

स्लेवस्टॉक पालीओल का उत्पादन करता है । प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है ।

### घरेलू उद्योग

- 21 मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि. चैत्रे द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई है । याचिकाकर्ता कंपनी भारत में 3000 से 4000 आण्विक भार के लचीले स्लेवस्टॉक पालीओल का एकमात्र उत्पादक है । इसलिए, वे संबद्ध वस्तु के 100% घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं । उसकी स्थिति के विरोध में कोई तर्क नहीं दिया गया है इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि मै मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि. नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" का प्रतिनिधित्व करता है ।

### इ पाटन तथा सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमतों पर किए गए दावों की जांच

#### सामान्य मूल्य

- 22 सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (1)(ख) के अधीन एक वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है कि :
- "(i) समान वस्तु के लिए जब निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग से आशय हो, व्यापार की साधारण स्थिति में, तुलनीय कीमत जिसे उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार निश्चित किया गया है"; अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य स्थिति में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो, अथवा जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की विशेष बाजार दशा या कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की एक उपयुक्त तुलना की स्थिति न हो तब सामान्य मूल्य निम्न में से कोई एक होगा:

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसे निर्यातक देश या क्षेत्र अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किया गया था जैसा कि उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है; अथवा
- (ख) प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागत तथा लाभों के लिए तर्कसंगत योग के साथ मूल देश में उल्लिखित वस्तु की उत्पादन की लागत जैसा कि उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित किया गया है;"

23 धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सभी ज्ञात निर्यातकों को एक प्रश्नावली भेजी थी । नई दिल्ली में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को भी जांच प्रारंभ करने की सूचना दी गई थी तथा उनके देशों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने हेतु सलाह देने के लिए अनुरोध किया गया था । केवल निम्नांकित निर्यातकों से उत्तर प्राप्त हुए थे:

- (i) मै. एस के सी लि., कोरिया
- (ii) मै. डाव क्विमिका एस.ए., ब्राजील
- (iii) मै. जिन हुआ कैमिकल्स (ग्रुप) कार्पोरेशन, चीन
- (iv) मै. बेयर पाली यूरेथीन्स, ताईवान

#### कोरिया गणराज्य

24 मै. एस के सी लि., कोरिया ने प्रश्नावली में घरेलू बिक्री, भारत को निर्यात, समायोजन, बिक्री कीमत संरचना, उत्पादन की लागत इत्यादि से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी है । उत्पादन की लागत तथा घरेलू बाजार के लिए इकाई बिक्री कीमत से संबंधित उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर घरेलू बिक्री व्यापार की साधारण स्थिति में प्रतीत होती है । प्रारंभिक जांच परिणाम के उद्देश्य से प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री कीमत पर विचार किया है जो सूचना के सत्यापन पर निर्भर है । निर्यातक ने छूट, अंतर्देशीय भाड़ा, स्टोरेज तथा अन्य लागतों के लेखों पर समायोजन दर्शाया है । सत्यापन के अधीन इनकी अनुमति दी गई है अतः सामान्य मूल्य \*\*\* अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन बनता है ।

**ब्राजील**

- 25 मै. डाव क्विमिका एस.ए., ब्राजील ने प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्रश्नावली पर सूचना उपलब्ध नहीं की है। उन्होंने केवल कुछ सामान्य टिप्पणियां की हैं। प्राधिकारी ब्राजील के निर्यातकों को असहयोगी पाते हैं तथा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर होने के लिए बाध्य हैं। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर उत्पादन को परिकालित लागत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस उद्देश्य के लिए प्रोपीलीन की लागत सितंबर-दिसंबर 2002 की अवधि के लिए ली गई है जैसा कि एसियन कैमिकल न्यूज़ में दी गई थी। लागत के अन्य तत्वों के लिए, प्राधिकारी ने तर्कसंगत रूप से उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार किया है। अतः सामान्य मूल्य \*\*\* अमरीकी डॉलर/प्रति मीट्रीक टन निर्धारित किया गया है।

**चीन जनवादी गणराज्य**

- 26 केवल एक निर्यातक मै. जिन हुआ कैमिकल्स (ग्रुप) कार्पोरेशन चीन ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है, तथापि, उन्होंने प्रश्नावली में मांगी गयी सभी जानकारीयां उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने निम्नांकित जानकारीयां / दस्तावेज़ उपलब्ध कराये हैं:

- (i) अधिकरण समझौता,
- (ii) घरेलू बिक्री के संबंध में बीजक (चीन में),
- (iii) उत्पाद हैंडबुक,
- (iv) कंपनी का परिचय,
- (v) भारतीय बाजार में बिक्री कीमत संबंधी एक विवरण

प्राधिकारी पाते हैं कि चीनी निर्यातक के उत्तर समग्रतः अपूर्ण हैं क्योंकि इसमें प्रश्नावली में चाही गई जानकारी शामिल नहीं है। निर्धारित प्रारूप में घरेलू बिक्री के पूर्ण ब्यौरे, प्रारूप में भारत तथा अन्य देशों को की गई बिक्री के पूर्ण ब्यौरे, समायोजन - बिक्री कीमत संरचना, उत्पादन की लागत इत्यादि उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यातक ने इस धारण कि वे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में व्यापार करते हैं के खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया

है। इसलिए प्राधिकारी को नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर उत्पादन की परिकलित लागत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस उद्देश्य से प्रोपीलीन की लागत सितंबर-दिसंबर 2002 की अवधि के लिए ली गई थी। लागत के अन्य तत्वों के लिए, प्राधिकारी ने तर्कसंगत रूप से उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार किया है। अतः सामान्य मूल्य \*\*\* अमरीकी डॉलर / प्रति मीट्रीक टन निर्धारित किया गया है।

### ताईवान

27 ताईवान से केवल एक निर्यातक अर्थात् मै. बेयर पालीयूरेथीन्स, ताईवान ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है, हालांकि उन्होंने प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से प्रश्नावली में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने केवल कुछ सामान्य टिप्पणियां की हैं। प्राधिकारी ताईवान के निर्यातकों को सहयोगी मानते हैं तथा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर होने के लिए बाध्य हैं। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर उत्पादन की परिकलित लागत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस उद्देश्य से प्रोपीलीन की लागत सितंबर-दिसंबर 2002 की अवधि के लिए ली गई है जैसा कि एसियन कैमिकल न्यूज़ में दी गई थी। लागत के अन्य तत्वों के लिए, प्राधिकारी ने तर्कसंगत रूप से उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार किया है। अतः सामान्य मूल्य \*\*\* अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन निर्धारित किया गया है।

### निर्यात कीमत

#### कोरिया गणराज्य

28 मै. एस.के.सी. का. लि., कोरिया ने प्रश्नावली में भारत को निर्यात किए गए \*\*\*अमरीकी डॉलर/मीट्रीक टन से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। छूट, पैकिंग, भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, शिपिंग प्रभार जिनकी दावे के रूप में अनुमति दी गई है की वजह से समायोजन दर्शाया गया है। ऋण लागत के कारण \*\*\*अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन का समायोजन किया



गया है जैसा कि बीजक में प्रदर्शित है । निवल निर्यात कीमत \*\*\* अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन पर पहुंच गई है ।

### ब्राजील

- 29 ब्राजील के किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत संबंधी जानकारी नहीं दी है । प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा निर्यातक कीमतों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना पर विचार किया है जो कि मै. इंटरनेशनल डाटा सर्विसेज, मुंबई से प्राप्त किए गए अगोपनीय याचिका में उल्लिखित आंकड़ों पर आधारित है । याचिकाकर्ता ने अनुमत समुद्री भाड़े तथा बीमा के कारण सी आई एफ कीमतों से समायोजन किया है । निवल निर्यात कीमत \*\*\* अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन पर पहुंच गई है ।

### चीन जनवादी गणराज्य

- 30 चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत संबंधी जानकारी नहीं दी है । प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा निर्यातक कीमतों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना पर विचार किया है जो कि मै. इंटरनेशनल डाटा सर्विसेज, मुंबई से प्राप्त किए गए अगोपनीय याचिका में उल्लिखित आंकड़ों पर आधारित है । याचिकाकर्ता ने अनुमत समुद्री भाड़े तथा बीमा के कारण सी आई एफ कीमतों से समायोजन किया है । निवल निर्यात कीमत \*\*\* अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन पर पहुंच गई है ।

### ताईवान

- 31 ताईवान के किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा निर्यातक कीमतों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना पर विचार किया है जो कि मै. इंटरनेशनल डाटा सर्विसेज, मुंबई से प्राप्त किए गए अगोपनीय याचिका में उल्लिखित आंकड़ों पर आधारित है । याचिकाकर्ता ने अनुमत समुद्री भाड़े तथा बीमा के कारण सी आई एफ कीमतों से समायोजन किया है । निवल निर्यात कीमत \*\*\* अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन पर पहुंच गई है ।

### कोरिया गणराज्य से अन्य निर्यातक

32. मै. एस.के.सी. का. लि. को छोड़कर कोरिया गणराज्य किसी अन्य निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने अन्य निर्यातकों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर उत्पादन की परिकलित लागत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस उद्देश्य से, एसियन केमिकल न्यूज़ में सितंबर-दिसंबर 2002 की अवधि में दी गई प्रोपीलीन लागत को लिया गया है। लागत के अन्य तत्वों के लिए प्राधिकारी ने तर्कसंगत रूप से उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार किया है। इस प्रकार सामान्य मूल्य \*\*\*अमरीकी डॉलर/मीट्रीक टन निर्धारित किया गया है। जहां तक अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का संबंध है, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना, जो कि मै. इंटरनेशनल डाटा सर्विसेज़ मुंबई से प्राप्त किए गए अगोपनीय याचिका में उल्लिखित आंकड़ों पर आधारित है पर विचार किया है। याचिकाकर्ता ने अनुमत समुद्री भाड़े तथा बीमा के कारण औसत सीआईएफ कीमतों से समायोजन किया है। कोरिया गणराज्य के अन्य निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत \*\*\* अमरीकी डॉलर/प्रति मी. टन हो गई है।

### पाटन मार्जिन

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण को प्रशासित करने वाले सिद्धांत नियमावली के अनुबंध - 1 में दिए गए हैं। सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के संबंध में व्यापार के समान स्तर पर गणना तथा तुलना कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत से की गई है। सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत जिनके निर्धारण के ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं, पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नांकित बनता है:

क्र. संख्या	देश	निर्यातक का नाम	पाटन मार्जिन%
1.	कोरिया गणराज्य	मै. एसकेसी क. लि.	39.91
2.	कोरिया गणराज्य	अन्य निर्यातक	70.34
3.	ब्राजील	सभी निर्यातक	107.50
4.	चीन जन. गण.	सभी निर्यातक	82.53
5.	ताईवान	सभी निर्यातक	88.36

## च. क्षति

34. पाटन रोधी नियमावली के नियम 11 के अनुसार:

"क्षति का निर्धारण:

- (1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में, प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त परिणामों को रिकार्ड किया जाएगा कि भारत में ऐसी वस्तुओं के आयात से किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति तो नहीं होगी अथवा इसका खतरा तो नहीं है अथवा इससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न तो नहीं होगी;
  - (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी, सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू उद्योग में कीमत पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है तथा इन नियमों के अनुबंध 2 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार क्षति का खतरा, घरेलू उद्योग की स्थापना में आई वास्तविक बाधा तथा पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे ।
35. क्षति के निर्धारण के लिए सिद्धांत पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -2 में दिए गए हैं जिसके अनुसार:
- (i) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी ।
  - (ii) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में या तो निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है । नियम 18 के उपनियम (2) में यथासंदर्भित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या अन्यथा ऐसे आयातों का

प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना है या कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त रूप से बढ़ गई होती ।

### 36. याचिकाकर्ता के विचार

क्षति तथा कारणात्मक संबंध से संबंध से संबंधित याचिकाकर्ताओं के विचार इस परिणाम के भाग ख में दिए गए हैं तथा संक्षिप्तता के उद्देश्य से इन्हें नहीं दोहराया जा रहा है ।

### 37. निर्यातकों, आयातकों तथा उपयोगकर्ता उद्योग संघ के विचार

निर्यातकों, आयातकों तथा उपयोगकर्ता उद्योग संघ के क्षति तथा कारणात्मक संबंध से संबंधित विचार इस परिणाम के भाग ख में दिए गए हैं तथा संक्षिप्तता के उद्देश्य से इन्हें नहीं दोहराया जा रहा है ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में याचिकाकर्ता, निर्यातकों, आयातकों तथा उपयोगकर्ता के विचारों पर ध्यान दिया है । प्राधिकारी ने क्षति के विभिन्न मानदण्डों से संबंधित सूचनाओं की जांच की है जो निम्नानुसार है:

### संबद्ध देशों से आयात:

39. याचिका के अनुसार, संबद्ध देशों से आयात तथा कुल आयात निम्नानुसार थे:

आयात की मात्रा	2000-2001	2001-2002	अप्रैल-दिसंबर 2002
संबद्ध देश	48	67.20	3412.27
अन्य देश	1003.95	4486.07	49.42
कुल	1051.95	4553.27	3461.69
संबद्ध देश का %तता अंश	4.56	1.48	98.57

याचिकाकर्ता ने बताया है कि आयात आंकड़े मै. इंटरनैशनल डाटा सर्विसेज़, मुंबई से प्राप्त किए गए हैं जो कि सीमाशुल्क विभाग की प्रतिदिन की सूची पर आधारित है परंतु यह कुछेक पतनों को कवर करता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र आयात याचिका में तालिकाओं में दर्शाए गए आयातों से अधिक होंगे। इसके अलावा यह बताया गया है कि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों का पृथक आबद्ध कोड नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योग को गौण स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार प्राप्त हुई सूचना की जांच की है और यह पाया है कि आई टी सी एच एस एन वर्गीकरण 39072000 के तहत आयात विभिन्न प्रकार के पॉलीओल को कवर करते हैं। यह मानना कठिन होगा कि इस वर्गीकरण के अंतर्गत सभी आयात विचाराधीन उत्पाद अर्थात् 3000-4000 आणविक भार के लचकीले स्लेबस्टॉक पॉलीओल से संबद्ध होंगे। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार पॉलीओल के सभी वर्गों के आयात निम्न प्रकार हैं:

आयात की मात्रा मी.टन	2000-2001	2001-2002	अप्रैल-दिसंबर 2002
संबद्ध देश	1180.29	1307.72	5791.57
अन्य देश	14208.96	25785.95	10438.00
कुल	15389.25	27093.67	16229.57

प्राधिकारी ने द्वितीयक स्रोतों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों पर विचार किया है। तथापि, इन आंकड़ों में केवल कुछेक पत्तन ही शामिल हैं। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें दूसरे पॉलीओल के आयात शामिल थे। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों पर विचार किया है और जहां कहीं भी निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वास्तविक आयातों को अधिक दर्शाते हैं वहां ऐसे आंकड़ों पर विचार किया गया है। तदनुसार प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के आयात निम्नानुसार हैं:

आयात की मात्रा मी.टन	2000-2001	2001-2002	अप्रैल-दिसंबर 2002
संबद्ध देश	48	1060.6	3412.27
अन्य देश	3276.31	4486.07	120.7

कुल	3324.31	5546.67	3532.34
संबद्ध देश का %तता अंश	1.44%	19.12%	96.6%

प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । पाटित आयात वर्ष 2000-01 में 48 मी. टन से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 1060.6 मी. टन और जांच अवधि के दौरान 3412.27 मी. टन हो गए । 2000-2001 में 1.44% से जांच अवधि के दौरान 96.6% की वृद्धि हुई है । अतः संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है ।

#### बाजार अंश:

40. प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और संबद्ध देशों से आयात निम्न प्रकार से रहे हैं:

मात्रा (मी.टन)	2000-2001	2001-2002	अप्रैल-दिसंबर 2002 (जांचावधि)	जांचावधि सालाना
आयात	3324.31	5546.67	3532.34	4709.79
घरेलू बिक्री	***	***	***	***
मांग	***	***	***	***
घरेलू उद्योग का हिस्सा %	68.41	55.20	66.11	66.11
संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा(%)	0.46	8.57	32.74	32.74

प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात हिस्सा 2000-2001 में 0.46% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 32.74% हो गया है । इस प्रकार देश में उत्पाद की मांग के संबंध में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि हुई है ।

**उत्पादन और क्षमता उपयोग:**

41. प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्न प्रकार से रहा है:

	2000-2001	2001-2002	(जांचावधि)
क्षमता	11250	11250	8438
उत्पादन	7316.15	7129.45	6037
क्षमता उपयोगिता %	65.03	63.37	71.54

प्राधिकारी पाते हैं कि पूर्व वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है ।

**बिक्री मात्रा:**

42. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा वर्ष 2000-01 में \*\*\* से बढ़कर जांच अवधि में \*\*\* हो गई और सूचीबद्ध आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	बिक्री मात्रा मी.टन	इकाई मूल्य रुपए/मी.टन
2000-2001	100	100
2001-2002	95	92.53
अप्रैल-दिसंबर 2002 (जांचावधि- वार्षिक )	127.6	91.05

प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है । तथापि, इकाई मूल्य वसूली अत्याधिक गिर गई है।

## माल सूची

43. समाप्त स्टॉक की माल सूची निम्न प्रकार से रही है:

2000-2001	2001-2002	(जांचावधि)
100 मी.टन	130.33 मी.टन	26.84 मी.टन

सूचीगत

प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा रखी गई तैयार वस्तुओं की माल सूची में मार्च 2002 को समाप्त पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि की समाप्ति पर महत्वपूर्ण गिरावट आयी है ।

## कीमत कटौती :

44. प्राधिकारी पाते हैं कि पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती निम्न प्रकार से रही है:

	चीन	एसकेसी कोरिया	कोरिया अन्य	ताईवान	ब्राजील
औसत निवल बिक्री घरेलू उद्योग की आय	***	***	***	***	***
आयात का पहुंच मूल्य	***	***	***	***	***
एनएसआर के % के अनुसार कीमत कटौती	12.31	8.20	8.59	14.57	23.05



**रोजगार:**

45. मानवशक्ति वर्ष 2000-2001 में 576 से अत्याधिक घटकर जांच अवधि के दौरान 430 हो गई है ।

**मजदूरी:**

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोई वृद्धि या प्रोत्साहन प्रदान करने में अक्षम रहा है । वैधानिक लाभांश के अलावा सभी लाभांशों को अत्याधिक कम कर दिया गया है । कंपनी औद्योगिक (विवाद और विनियमन) अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत श्रमिक यूनियन के साथ नए मजदूरी समझौते को लागू करने की भी स्थिति में नहीं है जो कि प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए बहुत से अभ्यावेदनों के बावजूद जनवरी 2001 से अपेक्षित है।

**लाभप्रदता:**

47. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं की प्रति इकाई बिक्री पर नीचे दी गई सूचना के अनुसार प्रत्यक्ष घाटा उठाया है:

वर्ष	बिक्री मूल्य (रूपए/लाख)	बिक्री की लागत (रूपए/लाख)	प्रति इकाई लाभ/हानि
2000-01	***	***	(-)3.59%
2001-02	***	***	(-)9.71%
अप्रैल-दिसंबर 2002(जांच अवधि)	***	***	(-)5.37%

प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर प्रति इकाई घाटा पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है । कंपनी द्वारा घाटा उठाने के कारण निवेशों पर आय नकारात्मक है ।

### गंवाई गई संविदाओं का साक्ष्य

48. घरेलू उद्योग ने चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए आदेशों की प्रतियों के रूप में आदेश गंवाने के कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं ।

### नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव:

49. प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर नकद घाटा उठाया है जिससे कुल मिलाकर कंपनी की नकद प्रवाह स्थिति को क्षति पहुंची है।

### संवृद्धि

50. प्राधिकारी पाते हैं कि घाटे के कारण घरेलू उद्योग के लिए कोई नया निवेश करना व्यवहार्य नहीं होगा ।

### क्षति संबंधी निष्कर्ष :

51. उपर्युक्त विभिन्न आर्थिक कारकों पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं:

- (i) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उक्त उत्पाद की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है;
- (ii) कुल मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2000-01 की तुलना में कम हुआ है।
- (iii) घरेलू उद्योग पाटित आयातों से हुई कीमत कटौती के कारण क्षति पहुंची है।
- (iv) कम बिक्री वसूली के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से घाटा उठाया है ।

- (v) घरेलू उद्योग मौजूदा मानव शक्ति को बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा है । यह अपने कर्मचारी संघ के साथ मजदूरी के संबंध में नए संविदा पत्र पर समझौता करने में सक्षम नहीं रहा है ।
- (vi) वित्तीय घाटे के कारण घरेलू उद्योग अपने व्यवसाय में और निवेश करने में सक्षम नहीं है ।
- (vii) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। बिक्री मात्रा बढ़ी है । माल सूची स्तर नीचे आ गया है ।
- (viii) तथापि, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा और घटी हुई माल सूची में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण क्षति उठाई है । पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती और वित्तीय घाटा हुआ ।

### क्षति का संचयी मूल्यांकन

52. अनुबंध 2 (iii) के अनुसार उन स्थितियों में जहां किसी उत्पाद के एक से अधिक देश से आयातों को एक ही समय पाटनरोधी जांच का विषय बनाया जाता है, प्राधिकारी द्वारा ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। केवल तब इससे यह निर्धारित होता है कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित किया गया पाटन मार्जिन 2% से अधिक है जिसे निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का 3% है - और (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिसपर्धा की शर्तों के आलोक में उचित है। प्राधिकारी ने पाया है कि प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा भी 3% से अधिक है । प्राधिकारी ने आयातित उत्पादों और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के बीच प्रतिसपर्धा की शर्तों के आलोक में घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तु पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना भी उचित समझा है । प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग पर क्षति का संचयी प्रभाव हुआ है ।

## छ. कारणात्मक संबंध

53. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 2 के नियम (v) के अनुसार घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है। नियमावली के अनुबंध 2 के पैरा (iv) में यथानिर्दिष्ट संगत सूचकांकों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है।

54. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कारणात्मक संबंध के बारे में व्यक्त किए गए विचारों, जिनका पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है, पर विचार किया है। उपर्युक्त विभिन्न आर्थिक मापदंडों की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं :

- (i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- (ii) संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है।
- (iii) घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से अत्यधिक कम रही है। पाटित आयातों के कारण निवल बिक्री वसूली क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) से कम रही है।
- (iv) घरेलू उद्योग ने कम कीमत वसूली के कारण वित्तीय घाटा उठाया है।
- (v) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कम पहुंच मूल्य के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने उत्पादों के लिए एक उचित और तर्कसंगत कीमत वसूल करने में असफल रहा है। इसके कारण निदेश पर नकारात्मक आय हुई।
- (vi) उपर्युक्त आर्थिक मापदंड संचयी और समग्र रूप से इस बात की पुष्टि करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठाई है।
- (vii) संबद्ध वस्तु की मांग कम नहीं हुई है परंतु इसके बजाय यह बढ़ी है और इसलिए मांग संकुचन को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। उद्योग में किसी तकनीकी विकास या ऐसे किसी अन्य कारक को नोटिस नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती थी। घरेलू उद्योग पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान उच्च क्षमता उपयोग को प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इसलिए क्षति के लिए कम उत्पादकता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(ज) भारतीय उद्योग के हित

55. पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनःस्थिति लाना है, जो कि देश के सामान्य हित में है ।
56. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करने वाले प्रयोक्ता उद्योग के कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है से और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का हास रुकेगा और उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

(झ.) निष्कर्ष

57. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- (i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;
- (ii) घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति उठाई है; और
- (iii) वास्तविक क्षति संचयी रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

58. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर अंतिम निर्धारण होने तक अनंतिम रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक मानते हैं । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन उपर्युक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है । प्राधिकारी यह सिफारिश करने का प्रस्ताव करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन से अधिक नहीं

होनी चाहिए और जो भी कम है और जिसे यदि लगाया जाए तो उससे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित बिक्री कीमत से तुलना की गई है ।

59. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि अंतिम निर्धारण होने तक चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और ब्राजील के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण की अनुसूची 1 के अध्याय शीर्ष 3907 2000 के अंतर्गत आने वाले 3000 से 4000 के आणविक भार के फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलिओल के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित धनराशि और अमरीकी डॉलर/कि.ग्राम में संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य का अंतर होगा ।

क्र. सं.	उप शीर्ष	माल का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.
1.	3907. 2000	लचकीला स्लैबस्टॉक पोलिओल	3000 से 4000 आणविक भार	चीन जन. गण.	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1463.71	मी.टन	अमरीकी डॉलर
2	3907. 2000	लचकीला स्लैबस्टॉक पोलिओल	3000 से 4000 आणविक भार	कोई देश	चीन जन. गण.	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1463.71	मी.टन	अमरीकी डॉलर
3	3907. 2000	लचकीला स्लैबस्टॉक पोलिओल	3000 से 4000 आणविक भार	कोरिया गणराज्य	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1463.71	मी.टन	अमरीकी डॉलर
4	3907. 2000	लचकीला स्लैबस्टॉक पोलिओल	3000 से 4000 आणविक भार	कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1463.71	मी.टन	अमरीकी डॉलर
5	3907. 2000	लचकीला स्लैबस्टॉक पोलिओल	3000 से 4000 आणविक भार	ताइवान	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1463.71	मी.टन	अमरीकी डॉलर
6	3907. 2000	लचकीला स्लैबस्टॉक पोलिओल	3000 से 4000 आणविक भार	कोई देश	ताइवान	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1463.71	मी.टन	अमरीकी डॉलर
7.	3907. 2000	लचकीला स्लैबस्टॉक पोलिओल	3000 से 4000 आणविक भार	ब्राजील	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1463.71	मी.टन	अमरीकी डॉलर
8	3907. 2000	लचकीला स्लैबस्टॉक पोलिओल	3000 से 4000 आणविक भार	कोई देश	ब्राजील	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1463.71	मी.टन	अमरीकी डॉलर

60. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 9 और 9क के तहत लगाए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्कों सहित

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलन योग्य मूल्य होगा ।

(ल) आगे की प्रक्रिया

61. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों से इन निष्कर्षों के बारे में टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम निष्कर्षों में विचार किया जाएगा;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ताओं तथा अन्य ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से लिखा जा रहा है, जो प्रारंभिक परिणामों की तारीख से 40 दिनों के अंदर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है;

(ग) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों को मौखिक अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे जिन्हें उसके बाद लिखित में प्रस्तुत करना होगा;

(घ) प्राधिकारी आवश्यक सीमा तक और आगे जांच करेंगे;

(ङ) प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों को घोषणा करने से पूर्व आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया जाएगा ।

अभिजित सेनगुप्ता, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2003

**Preliminary Findings**

**Subject : Anti-dumping investigation concerning import of Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000 to 4000 from China PR, Republic of Korea, Taiwan and Brazil.**

**No. 14/4/2003-DGAD.—** The Government of India having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

**A. PROCEDURE**

2. The procedure described below has been followed:-

- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Manali Petrochemicals Ltd., Manali, Chennai representing the domestic industry, alleging dumping of Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000 to 4000 (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from People's Republic of China, Republic of Korea, Taiwan and Brazil (hereinafter referred to as subject countries);
- (ii) The preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was thereafter, considered as properly documented;
- (iii) The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of dumping application made by the petitioners before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;
- (iv) The Authority issued a Public Notice dated 21<sup>st</sup> May, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000 to 4000 covered under Chapter heading/subheading 3907.20, 3907.99 and 3907.91 of Schedule I of the Customs Tariff Act.



- (v) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing.
- (vi) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassies of subject countries in India.
- (vii) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following exporters: -

M/s S.K. Oxichemical Co Ltd.  
23-10. Yoido Dong  
Yongdungpo-GU, Seoul  
South Korea 180-0101

M/s Bayer Poly urethanes Taiwan Ltd.  
2F290 Chung Hsiao E Rd. Sec 4  
Taipei, Taiwan.

Zhejiang Sanhuan Chemical Company Ltd.  
No. 1007.jiu Ling Xi Road  
Yongkang  
Zhejiang 32130. P.R. China.

Dow Quimica S.A.  
Rua Alexander Dumas  
1671 P.P. Box 9037  
010065 – 970 Sao Paulo  
Brazil.

- (viii) The Embassies of subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;
- (ix) The questionnaire was sent to the following importers of subject goods:

1. M/s. Feather Foam Enterprises Pvt. Ltd.  
Plot No.257, Saily  
Umarkvi Road  
Silvassa – 396 230 (UT of DNH)

2. M/s. Natson Foam Mfg. P Ltd.  
5, Panchayat Bhavan, Bhadras  
Ahmedabad-1.
3. M/s. Dura Foam Industries Pvt Ltd  
123, Indl. Estate, Silvassa  
Union Territory of Dadra-Nagar Haveli
4. M/s. Surya Foam  
Sedarapet Main Road  
Sedarapet  
Pondicherry.
5. M/s. DP Foam Private Ltd  
13, Rangapillai St.,  
P B No.130  
Pondicherry-605 001.
6. M/s. Kurlon Ltd.  
Jalahalli Camp Road  
Yeshawanthpur  
Bangalore 560 022.
7. M/s. Aparna Polyproducts Ltd.,  
452, Ganapati Plaza  
M.I. Road  
Jaipur 302 001 (Rajasthan)
8. M/s. Tirupati Foams Ltd  
502, Harekrishna Complex  
Opp. Kothawala Flats  
Pritam Nagar, Ellis Bridge  
Ahmedabad – 380 006.
9. M/s. Soft Foam Industries Pvt. Ltd  
Survey No.3852, Medchal Indl. Area  
R.R. District 501 401 (AP)
10. M/s. Madras Polymoulds  
28, C&D Krishnaswamy Avenue  
Mylapore  
Chennai-4.
11. M/s. Sheela Foam Private Limited  
37/2, Site No.IV, Sahibabad Indl. Area  
Sahibabad-201010  
Ghaziabad (U.P.)

12. M/s. J J Foams Pvt. Ltd  
B-12/2, Site-IV, Sahibabad Indl. Area  
Sahibabad (Dist. Ghaziabad) U P
13. M/s. M H Polymers Pvt. Ltd  
B 15, Site B, Suraj Pur Indl. Area  
Tehsil, Dadri  
Dist. Ghaziabad (UP)
14. Sandeep Foam Industry Pvt. Ltd.  
Unit – II, B-374 Main Road  
Gajipur Village,  
Delhi – 110 096
15. Arvind International Ltd.  
E95-96 & 76-78 RIICO Industrial Area  
Bagru Extension  
Bagru 303 007  
Rajasthan
16. Dura Puf (Silvassa) Pvt. Ltd.  
121, Piparia Industrial Estate,  
Union Territory of Dadra & Hagar Haveli  
Via. Wapi (W. Rly.), Silvassa
17. Joy Foam Pvt. Ltd.  
55-B/3, Sipco industrial Estate,  
Ranipet
18. Devi Foam Pvt. Ltd.,  
391-A, Gonde Tal, Igatpur,  
Nasik-Mumbai Road,  
Nisik,  
Maharashtra,
19. Swiss Foam Industries  
823 & 8254, GIDC Phase – II,  
Chattral, Kalol,  
Gujarat.
20. Cozy Foams Pvt Ltd.,  
Plot No. 17, Survey No. 820/F,  
Village –Mahirn, (Chintjiparda)  
Palghar, Dist – Thane.
21. Foam Home (India) Pvt. Ltd.,  
H-30/2 MIDC Tajoja  
Maharashtra.

22. Romega Foam Pvt. Ltd,  
36 Canal Road,  
Kudapakkam,  
Villanur  
Pondicherry – 605 110
23. Alfa Chemical Corporation,  
Godown No. 19,  
Shiv Compoundm,  
Rahanal Village,  
Bhiwandi 421 302  
Dist - Thane.
24. Polyurethane Association of India  
Mr. K. Ramamurthy  
Secretary  
Flat 7, III Floor, Shakti Mahal  
New No. 24 (Old 41), First Main Road,  
CIT Colony, Mylapore,  
Chennai – 600 004.

- (x) Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished;
- (xi) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- (xii) Some of the interested parties requested for extension in time to file their response to the questionnaire which was granted upon due cause shown;
- (xiii) \*\*\*\*\* in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- (xiv) The investigation covered the period from 1<sup>st</sup> April 2002 to 31<sup>st</sup> December, 2002.
- (xv) Copies of initiation notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

#### **B. PETITIONER'S VIEWS**

3. The petitioner has made the following major arguments in their submissions:-

- (i) The petition is filed against the subject products exported from or originating in China, Korea, Brazil and Taiwan (hereinafter also referred to as the subject country/countries).
- (ii) MPL is sole manufacturer of propylene oxide in India, starting from basic raw material propylene, which in turn is processed to manufacture flexible polyol.
- (iii) This product is used to produce flexible slabstock foam. There are no substitutes for this product.
- (iv) Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000 used in the manufacture of Slabstock foam. Details of articles that petitioner is capable of producing product range include propylene oxide, propylene glycol and various grades of polyether polyols (flexible, rigid and elastomer, speciality grades). The petitioner does not import any goods similar to their produce to trade.
- (v) The subject products manufactured in India by the petitioners are commercially and technically substitutable to the imported products. Hence all conditions of 'like-article' are satisfied.

#### 4. On Dumping

- (i) We have tried to get information on prices of the subject goods in the domestic market of Korea, Taiwan and Brazil. We have also made efforts to get price lists of the exporters or evidence for their export prices to other countries. We have not been able to get any documentary evidence either with regard to the prices of the subject goods in the subject countries or the price list of the exporters either for sale in that country or for exports to other countries. In the light of the above constructed Normal Value in the subject countries is a good indicator of the Normal Value for the subject goods, particularly as the prices are determined on the basis of international prices of raw materials.
- (ii) In case of China, the provisions of Para 8 of Annexure I to the Anti-dumping Rules are applicable as several Members of the WTO including India have treated China as Non-market Economy in the last three years. Accordingly, the Hon'ble Authority may kindly apply the principles of Non-market Economy as laid down in Paras 7 & 8 of Annexure 1 to Anti-dumping Rules.

- (iii) We have not been able to ascertain the prices in third countries which can appropriately surrogate for prices prevailing in China for reasons in the aforesaid paras. As provided in the Rules, the Designated Authority may kindly adopt the prices based on prices payable in India for the purpose of initiation.
- (iv) The Export Price for subject country has been worked out on the basis of the import figures available with us along with their CIF values as detailed in Part I of this application. The subject countries are exporting the subject products into India at prices, which are significantly lower than their normal values.

## 5. On Injury

### i) Cumulative Assessment

The margins of dumping from each of the subject countries are more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than de minimis. Cumulative assessment of the effects of imports would be appropriate since the exports from the subject countries directly compete with each other and with the goods offered by the domestic industry in the Indian Market. The Authority is, therefore, requested to assess injury to the domestic industry from the subject countries cumulatively.

### ii) Market share of the imports from Subject countries

Market share of the imports from the subject countries as a percentage of the total imports has increased from 1.48% in the year 2001-2002 to 98.57% during the period of investigation. This is primarily due to the reason that the importers continue to import at dumped prices to the detriment of the Domestic Industry.

The market share of imports from the subject countries in the total demand has sharply risen from 0.59% during 2001-2002 to 32.90% during the period of investigation.

### iii) Changes in Market Share held by the Indian producers.

The market share of domestic industry has decreased from 87.25% in 2000-2001 to 66.43% in the period of investigation. However, during the period of investigation, there is some increase in the market share of the Domestic Industry as it has been selling at extremely low prices to match the prices of the dumped goods. This increase has been there primarily due to the imposition of anti-dumping

duties on other countries which had resulted in a better market access to the Domestic Industry until the dumped imports from the subject countries started coming into the country causing injury to the Domestic Industry.

**iv) Output, Productivity & Capacity Utilization**

The production as well as capacity utilization of the Domestic Industry increased in the period of investigation. This was primarily on account of the fact that the Hon'ble Designated Authority had initiated the investigations against four major suppliers on 21st September, 2001 and subsequently provisional anti-dumping duties were imposed on 11th February, 2002 vide Notification No. 17/2002- Customs. This remedial action by the Government of India allowed the Domestic Industry to improve its production and capacity utilization, which is likely to suffer again due to dumping by the subject countries.

**v) Sales Volume & Value**

There has been an increase in the sales volume of the domestic industry in the period of investigation as compared to the preceding year. However, it has to be seen that the Domestic Industry has been able to increase its sales only by reducing the prices which has resulted in losses despite improvement in sales volume. After achieving improvement in capacity utilization, the petitioner made special efforts to dispose of the production even at reduced prices so as not to be saddled with increased inventories.

**vi) Import Price Analysis**

The import price from the subject countries have declined considerably during the period of investigation. It may be noticed that the prices from the subject countries increased marginally in the year 2001-2002 over the preceding period but declined sharply from Rs. 43402 in 2000-2001 to Rs. 41857 during the period of investigation. The drop in prices has to be seen in the context of the drastic increase in imports from these sources during the period of investigation (from a mere 48 MT in 2000-2001 to Rs. 4550 (annualized) during the period of investigation).

**vii) Inventories**

The petitioner has been able to reduce its inventories only by clearing the production stocks at unremunerative prices.

(Indexed)					
YEAR 1		YEAR 2		POI (9 MONTHS)	
2000-2001		2001-2002		April 2002-Dec 2002	
Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
MTs.	Rs. lakhs	MTs.	Rs. lakhs	MTs.	Rs. Lakhs
100	100	130.33	126.44	26.84	23.82

#### viii) Price Undercutting

There has been a significant price undercutting by the dumped imports from the subject countries. The extent of undercutting is 11.64% in case of China, 7.90% for Korea, 13.92% for Taiwan and 22.46% for Brazil. It may be seen that even the current loss-making prices of the Domestic Industry are being undercut by the imports from the subject countries leading to further injury to the Domestic Industry.

#### ix) Profitability & Return on Investment

The domestic industry is suffering serious injury in the form of direct losses per unit of sale. It needs to be appreciated that it is this price factor along with the volume effect which has also led to extensive injury to the domestic industry. It is extremely damaging to the interests of the domestic industry to continue to suffer losses despite reasonably good level of production, capacity utilization and sales. This has also adversely affected our ability to raise capital and to plough funds for further expansion.

#### x) Evidence of Lost Contracts

The evidence of loss of contracts has been attached as Confidential Annexure.

#### xi) Employment & Wages

There has been a drastic decline in manpower from 576 in 2000-2001 to 430 during the period of investigation. Such is the adverse effect of dumping on the Domestic Industry that it has not been able to grant any increments or promotions during the last few years. All bonuses other than the statutory bonus have been reduced substantially. It may also be mentioned that the company is not in a position even to conclude a fresh wage settlement with the labour union under Section 12(3) of the Industrial (Disputes & Regulation) Act which has been due since January 2001 despite numerous representations made to the management.



**xii) Actual and Potential Negative Effect on Cash Flows**

Since the Flexible Slabstock Polyol has incurred a cash loss during the period of investigation, it has caused a severe strain on the cash flow position of the company as a whole.

**xiii) Ability to Raise Capital or Investments & Growth**

With the present state of financial losses, it would not be feasible for the Domestic Industry to make any further investments in this business.

**xiv) Magnitude of Margin of Dumping**

The Petitioners have estimated the margin of dumping based on the constructed cost method as 106.83% for China, 93.44% for Korea, 113.38% for Taiwan and 135.26% for Brazil. Details are in the Petition.

**6. CAUSAL LINK**

- (i) The imports of subject goods from sources other than China, Korea, Taiwan and Brazil are *de minimis* and are coming at higher prices during the period of investigation. Only the imports from China, Korea, Taiwan and Brazil are being made at dumped prices causing material injury to the petitioners.
- (ii) Demand for subject goods is showing a growth. Decline in demand is hence not a factor causing injury to the domestic industry. It may also be seen that the market size is growing and therefore, contracting demand is not a reason for the injury to the Domestic Industry.
- (iii) There is a single market for the subject goods where dumped imports compete directly with the goods produced by the domestic industry. The price determines the choice of supplier. The dumped goods are good substitutes for the like product of the indigenous producers. The imported product is sold to meet the similar commercial grades and standard specification, as domestically produced Flexible Polyol. The imported subject article and the domestically produced goods are like articles and are used for the same applications/end uses. Thus, pricing becomes the most important factor determining purchase of the article from either imported sources or domestic sources.

The share of domestic industry would have been much better but for dumped imports. The domestic industry is incurring losses on the sale of the subject products significantly. This can be directly attributed to the low priced imports from the subject countries as the domestic industry is always expected to match the prices offered by the importers from the subject countries. In the absence of dumped imports from the subject countries, the domestic industry would have been able to realize its fair selling price with a reasonable margin of profit.

### **C EXPORTERS', IMPORTERS', USERS' AND OTHER INTERESTED PARTIES' VIEWS**

7. Responses have been received from the following exporters: -

- (i) M/s SKC Co., Ltd. Korea
- (ii) M/s Dow Quimica S.A., Brazil
- (iii) M/s Jin Hua Chemicals (Group) Corporation, China
- (iv) M/s Bayer Polyurethanes, Taiwan

8. Only M/s SKC Co. Ltd. Korea has furnished response on the exporter's questionnaire.

9. M/s Dow Quimica S.A., Brazil has not furnished information on the questionnaire for the Authority to determine Normal Value and export price. They have, however, made following comments :

- (i) The Authority has allowed two weeks extension for filing the response but the time available was short to submit voluminous confidential data required.
- (ii) The applicants-MPL are the sole producers of Flexible Slabstock Polyol (FSP) in India. Anti dumping duty has been imposed only last year on the same product for exports from USA, Japan, Singapore and EU. Being sole producer, the intention of the petitioner appears to be monopolistic to enable them to dictate terms to the users.
- (iii) The market demand is 17,500 MT and growing at the rate of 12-15% p.a. The petitioner does not have the capacity to fulfill the demand. Petitioner produces different grades of Polyol for different applications. Balance demand needs to be supplemented by imports.
- (iv) Petitioner's production facility being highly uneconomic is the cause of their woes. The total volume of imports has in fact declined from 4553.27 MT in 2001-02 to 3461.69 during the POI. As regards to imports originating from Brazil, the question of

increase in imports does not arise as there were no imports from Brazil prior to the POI.

- (v) The claim of petitioner as regards having market share of 87.25% in 2000-01 does not appear to be correct when seen with the petition in the previous case. Further, with a market share as high as 87.25%, imports of the product can hardly have any effect on them.
- (vi) The average CFR for the period of investigation for import into India as per the data provided by the petitioner is US\$ 783.4 PMT. The supplies made by them are in bulk, thereby saving on drum packing and related costs.
- (vii) Petitioner's claims that reduction in price is a direct result of import is not true. It may be related to reduction in import duties since 2000-01.
- (viii) From the capacity data declared in their annual report and the market share data submitted by the petitioner in their earlier petition, it is clear that petitioner is mistaken about its FSP capacity / utilization. The petition proceeds on erroneous data and should be dismissed.
- (ix) Petitioner's profitability and return on investment cannot be based on one product (Hetero Polyol) which constitutes only 27% of its total revenue. It is the overall inefficient production process, uneconomic plant size and availability of raw material and other utilities that are the cause of the petitioner's woes and not the price of FSP.
- (x) The imports from subject countries have commenced only during the POI, in which case the losses suffered by the petitioner in the past cannot be due to imports from the subject countries.
- (xi) The petitioner has not used the imposition of safeguard duty or anti dumping duty imposed last year to improve its industrial competitiveness or efficiencies.
- (xii) Any imposition of anti dumping duty would only serve to further shield an uncompetitive and an inefficient sole domestic producer.

10. M/s Bayer Polyurethanes, Taiwan has not furnished information on the questionnaire for the Authority to determine Normal Value and export price. They have, however, made following comments :

- (i) We, as Bayer, are regular suppliers of the said product in your country with our registered brands Arcol 5613/Desmophen 7186

- for the last 25 years backed by our most reliable technical support.
- (ii) Our products are backed by well-known and established technology and have a consistent demand in the Indian market and are well accepted in the slabstock foam market in India. The consumers prefer to pay a premium for our superior international quality product and services.
  - (iii) We are very surprised and astonished about the petition as it is not and never was our intention to cause injury to the Indian Slabstock Polyol market and in fact, we strongly believe that we never did so.
  - (iv) According to reliable market information the current Indian Flexible Slabstock Polyol Market size is around 18,000 Mts. P.a. which has been growing at a double figure growth rate of about 11-12% for the past three years. The domestic production capacity is not enough to meet the growing demand, therefore, the shortfall has to be met via imports.
  - (v) The domestic producer, M/s Manali Petrochemicals Ltd., has been seeking protection continuously. The economic viability of their operations depends on efficient production process and a larger economic production capacity. But unfortunately they have not been able to achieve either in the last three years despite of the fact that a Safeguard and recent anti dumping from US, EU, Singapore and Japan was imposed to their favour.
  - (vi) Moreover, the Indian market already has the highest protection duty in the Asia Pacific region, 25% basic custom duty which actually cascades upto over 33% with the addition of other duties. Whereas, the per capita consumption of Flexible Slabstock Polyol in India is lowest in the region being almost 1/20<sup>th</sup> in comparison to China and other developing countries. Any further protection will increase costs to the consumer and hamper consumption growth / industrial growth of the segment.
  - (vii) Manali Petrochemicals Ltd., and Spic Organics have merged to form one company and have adopted a monopolistic attitude. Our presence in the market restricts monopolist practice and protects consumer by encouraging fair pricing. Any decision on imposing protection duty in this situation may develop into violation of the MRTP Act, 1969 and may tantamount to encourage monopolistic practice by the sole local producer.

The exporter had sought extension of time for submission of response with relevant data. Extension was granted by the Authority, however, no detailed response on questionnaire was received.

11. M/s Jin Hua Chemicals (Group) Corporation, China has not furnished complete response as required in the questionnaire. They have given following information / documents :

- i) Agency agreement
- ii) Invoices (in Chinese) in respect of domestic sales.
- iii) Product handbook
- iv) Introduction about the Company
- v) One statement about sales price in Indian market.

12. The Authority finds that the response of the Chinese, Brazilian and Taiwanese exporters is grossly deficient as it does not contain information as required in the questionnaire.

**Responses of importers / users association :**

13. M/s Sheela Foam Pvt. Ltd., Ghaziabad – They have furnished information on importer's questionnaire.

14. M/s Joy Foam Pvt. Ltd., Chennai – They have furnished information on importer's questionnaire and have also given following arguments :

- (i) Manali Petrochemical is an outdated old and uneconomic plant in size and any support at the cost of downstream producers is not going to make it viable.
- (ii) The financial problems of Manali Petrochemical are mainly arising out of the mis-management of the company as can be verified from the history of the company so far.
- (iii) Manali Petrochemical belongs to SPIC Group of Companies, which as per newspaper reports is facing financial difficulties and restructuring is being proposed for them.
- (iv) Under the circumstances it is for consideration whether temporary measures like Anti-dumping Duties could save the company.
- (v) It is our experience that the company has followed discriminatory sales policy. The monopolistic character of this producer, in a market, devoid of any competition even from importers of developing country would be ruinous for downstream manufacturers and their employees.
- (vi) Throughout the last year the price of Polyol has been fluctuating between USD 900 to USD 1050 per ton depending upon the seasonal variation. Even in the limited market that was open to us the prices had not changed substantially inspite of the fact that the Anti Dumping Duties virtually closed Indian Market for producers in all developing countries. It is only fair to assume that the basic price even under such circumstances in all developing countries remaining the same itself, is the indication that the prices fixed on commercial terms are existing now and are fair and reasonable.

15. M/s Star Foam Pvt. Ltd., Chennai – They have only furnished following comments :

- i) Manali Petrochemical cannot meet the all India marketing requirements.
- ii) The price of the Polyol is higher than the imported Polyol.

- iii) The quality of the product is not as the quality of the imported product.
- iv) Manali Petrochemical will not give Credit / Letter of Credit facility.
- v) We have imported the materials against 90 days Letter of Credit.

16. Polyurathene Association of India, Ghaziabad – They have made the following arguments :

- (i) M/s Manali Petrochemcals is the only manufacturer of Flexible Slabstock Polyol in India and they are in the habit of repeatedly seeking protection through anti dumping and other allied duties. They had sought protection under the Safeguard duty in 1998, thereafter they sought anti dumping duty in December, 2001.
- (ii) The petitioner is trying to block imports from the entire Polyol manufacturing companies in the world.
- (iii) The petitioner uses the inferior and obsolete technology and they are not commercially viable and competitive. They wish to avoid competition and want to monopolize the supply of Polyol in the country.
- (iv) The PU Foam Industry has no access to the information regarding the costing of Polyol at the end of the exporter or the petitioner.
- (v) Levy of anti dumping duty on Polyol will result in imports of PU Foam taking place at very low price from neighbouring countries like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Malaysia as these countries have very low custom duty.
- (vi) The PU foam industry comprises about 120 small scale units who work on a very low capital in a very competitive market. The industry is already facing stiff competition from other products like coir etc. and levy of anti dumping duty cannot be absorbed by the PU foam industry.

In view of above reasons, anti dumping duty should not be undertaken in public interest.

#### **D. EXAMINATION AND FINDINGS BY THE AUTHORITY**

17. The submission made by the petitioners, importers, exporters and other interested parties, to the extent filed before the Authority have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.

18. The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking shall be considered, on request, by the Authority in accordance with the Rules supra.

**Product Under Consideration**

19. The product under consideration in this investigation is Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000 to 4000 (hereinafter referred to as subject goods). The product is used to produce flexible slabstock foam. The product is covered under Customs heading 3907.20 of Schedule I of Customs Tariff Act and is also clear under Chapter Heading 3907.99 and 3907.91. This Custom classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. There are no arguments as regards the product under consideration.

**Like Article**

20. The petitioner has claimed that there is no difference between the product manufactured by them and the imported product. They have also stated that the subject product manufactured in India by the petitioner is commercially and technically substitutable to the imported product and hence all conditions of like article are satisfied. There are no arguments to oppose this claim. The Authority notes that the domestic industry produces Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000. The Authority holds the product being manufactured by the domestic industry to be like article to the subject goods being imported from subject countries.

**Domestic Industry**

21. The petition has been filed by M/s Manali Petrochemicals Ltd., Chennai. The petitioner company is the sole producer of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 in India. Therefore, they represent the 100% domestic production of the subject goods. There is no other argument to oppose this position. The Authority, therefore, considers that M/s Manali Petrochemicals Ltd. represents the 'Domestic Industry' within the meaning of Rule 2(b) supra.

**E. DUMPING & EXAMINATION OF CLAIMS MADE ON NORMAL VALUE & EXPORT PRICES****Normal Value**

22. Under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 normal value in relation to an article means:

“(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the

sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

23. The Authority sent questionnaire to all the known exporters of the subject countries for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). The Embassies of subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. The responses were received only from the following exporters:

- (i) M/s SKC Co., Ltd. Korea
- (ii) M/s Dow Quimica S.A., Brazil
- (iii) M/s Jin Hua Chemicals (Group) Corporation, China
- (iv) M/s Bayer Polyurethanes, Taiwan

#### **Republic of Korea**

24. M/s SKC Co. Ltd., Korea has furnished information in the questionnaire regarding domestic sales, exports to India, adjustments, sales price structure, cost of production etc. Based on the information furnished regarding cost of production and unit sales price for domestic market, the domestic sales appeared to be in the ordinary course of trade. For the purpose of preliminary findings, the Authority has considered the domestic sales price for determination of Normal Value, subject to verification of information. The exporter has shown adjustment on account of discounts, inland freight, storage and other costs. These have been allowed subject to verification. The Normal Value thus has been arrived at US\$ \*\*\*/PMT.

#### **Brazil**

25. M/s Dow Quimica S.A., Brazil has not furnished information on the questionnaire for the Authority to determine Normal Value and export price. They have only made some general comments. The Authority considers the exporters from Brazil as non-cooperative and is constrained to resort to facts available as per Rule 6(8) of Rules supra for determination of Normal Value. The Authority has determined Normal Value on constructed cost of production on the basis of evidence furnished by the petitioner. For this purpose, the



cost of Propylene has been taken for the period September-December, 2002 as reported in Asian Chemical News. For the other element of costs, the Authority has considered other evidence as reasonably available. The Normal Value is thus determined as US\$ \*\*\* / PMT.

#### People's Republic of China

26. Only one Chinese exporter M/s Jin Hua Chemicals (Group) Corporation, China has responded, however, they have not furnished complete response as required in the questionnaire. They have given following information / documents :

- i) Agency agreement
- ii) Invoices (in Chinese) in respect of domestic sales.
- iii) Product handbook
- iv) Introduction about the Company
- v) One statement about sales price in Indian market.

The Authority finds that the response of the Chinese exporter is grossly deficient as it does not contain information as required in the questionnaire. Full details of the domestic sales on the prescribed proforma, full details of sales to India on the proforma and sales to other countries, adjustments – sales price structure, cost of production etc. have not been furnished. Further, the exporter has also not furnished any evidence to rebut the presumption that they operate in Non-Market Economy conditions. The Authority is thus constrained to determine the Normal Value in respect of China on the basis of facts available as per Rule 6(8). The Authority has determined Normal Value on constructed cost of production on the basis of evidence furnished by the petitioner. For this purpose, the cost of Propylene has been taken for the period September-December, 2002 as reported in Asian Chemical News. For the other element of costs, the Authority has considered other evidence as reasonably available. The Normal Value is thus determined as US\$ \*\*\*/PMT.

#### Taiwan

27. Only one exporter from Taiwan viz., M/s Bayer Polyurethanes, Taiwan has responded, however, they have not furnished information on the questionnaire for the Authority to determine Normal Value and export price. They have only made some general comments. The Authority considers the exporters from Taiwan as non-cooperative and is constrained to resort to facts available as per Rule 6(8) of Rules supra for determination of Normal Value. The Authority has determined Normal Value on constructed cost of production on the basis of evidence furnished by the petitioner. For this purpose, the cost of Propylene has been taken for the period September-December, 2002 as reported in Asian Chemical News. For the other element of costs, the Authority has considered other evidence as reasonably available. The Normal Value is thus determined as US\$ \*\*\* / PMT.

**Export price****Republic of Korea**

28 M/s SKC Co. Ltd., Korea has furnished information on questionnaire regarding exports of \*\*\* MT of subject goods to India. Adjustments have been shown on account of discounts, packing, freight, inland freight, ocean freight, shipping charges which have been allowed as claimed. An adjustment of US\$ \*\*\* PMT on account of credit cost has also been made as reflected by the invoices. Net Export Price has been arrived at US\$ \*\*\* PMT.

**Brazil**

29. None of the exporters from Brazil have given information regarding export price. The Authority has considered the information furnished by the petitioner regarding export prices which is based on the data obtained from M/s International Data Services, Mumbai as stated in the non-confidential petition. The petitioner has made adjustments from the average CIF price on account of sea freight and insurance which have been allowed. The net export price arrived is US\$ \*\*\* PMT.

**People's Republic of China**

30. None of the exporters from PR China have given information regarding export price. The Authority has considered the information furnished by the petitioner regarding export prices which is based on the data obtained from M/s International Data Services, Mumbai as stated in the non-confidential petition. The petitioner has made adjustments from the average CIF price on account of sea freight and insurance which have been allowed. The net export price arrived is US\$ \*\*\* PMT.

**Taiwan**

31. None of the exporters from Taiwan have given information regarding export price. The Authority has considered the information furnished by the petitioner regarding export prices which is based on the data obtained from M/s International Data Services, Mumbai as stated in the non-confidential petition. The petitioner has made adjustments from the average CIF price on account of sea freight and insurance which have been allowed. The net export price arrived is US\$ \*\*\* PMT.

**Other exporters from Republic of Korea**

32. Except for M/s SKC Co. Ltd., no other exporter from Republic of Korea has responded to the questionnaire. For the other exporters, the Authority has determined Normal Value on constructed cost of production on the basis of evidence furnished by the petitioner. For this purpose, the cost of Propylene has been taken for the period September-December, 2002 as reported in Asian Chemical News. For the other element of costs, the

Authority has considered other evidence as reasonably available. The Normal Value is thus determined as US\$ \*\*\* / PMT. As regards export price for other exporters, the Authority has considered the information furnished by the petitioner regarding export prices which is based on the data obtained from M/s International Data Services, Mumbai as stated in the non confidential petition. The petitioner has made adjustments from the average CIF price on account of sea freight and insurance, which have been allowed. The net export price arrived for other exporters of Republic of Korea is US\$ \*\*\* PMT.

### **Dumping margin**

33. The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin are laid down in Annexure-I to the Rules. For the purpose of the fair comparison between the normal value and export price, the Authority has made calculations and comparisons at the same level of trade in respect of subject goods. Normal Value at ex-factory level has been compared with the export price at ex-factory level of subject goods. Considering the normal value and export price, determined as detailed above, the dumping margin comes as under:

S. No.	Country	Name of Exporter	Dumping Margin %
1.	Republic of Korea	M/s SKC Co. Ltd.	39.91
2.	Republic of Korea	Other exporters	70.34
3.	Brazil	All exporters	107.50
4.	People's Republic of China	All exporters	82.53
5.	Taiwan	All exporters	88.36

### **F. INJURY**

34. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

#### **"Determination of Injury:**

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules."

35. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti Dumping Rules lay down that :

(i) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

(ii) While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

### 36. Views of the petitioners

The views of the petitioner as regards injury and causal link are contained in Part B of these findings and these are not being repeated for the sake of brevity.

### 37. Views of Exporters, Importers and User Industry Association

The views of the Exporters, Importers and User Industry Association as regards injury and causal link are contained in Part C of these findings and these are not being repeated for the sake of brevity.

### Examination by the Authority:

38. The Authority has considered the views of the petitioner, exporters, importers and users as regards injury. The Authority has examined the information regarding various injury parameters as under:

### Imports from subject countries :

39. As per the petition, the imports from subject countries and total imports were as under :

Import Quantity	2000-2001	2001-2002	April-Dec.2002
Subject countries	48	67.20	3412.27
Other countries	1003.95	4486.07	49.42
Total	1051.95	4553.27	3461.69
%age Share of subject countries	4.56	1.48	98.57

The petitioner has stated that the import data have been obtained from M/s International Data Services, Mumbai, which is based on the Customs Daily List but covers only certain ports. The overall imports for the product under consideration will be higher than what has been reflected in the tables in the petition. Further, it has been stated that DGCI&S figures do not have a separate dedicated code and therefore, domestic industry had to rely upon secondary sources. The Authority has examined the information as per DGCI&S published data and observed that imports under ITC HSN Classification 3907 2000 cover different kinds of Polyol. It would be difficult to assume that the entire imports under this classification would relate to the product under consideration i.e. Flexible Slabstock Polyol of Molecular Weight 3000-4000. The imports of all categories of Polyol as per DGCI&S data are as under :

Import Quantity MT	2000-2001	2001-2002	April-Dec.2002
Subject countries	1180.29	1307.72	5791.57
Other countries	14208.96	25785.95	10438.00
Total	15389.25	27093.67	16229.57

The Authority has taken into consideration the import data furnished by the petitioner, which is based on the secondary sources. However, this data also covers only certain ports. The DGCI&S data could not be used as it contained imports of other Polyols. In the circumstances the Authority has considered imports figures as furnished by the petitioners and wherever the evidence furnished by the exporters and importers shows the actual imports to be higher, then such higher figures have been considered. Accordingly, the Authority finds that the imports of the subject goods are as under :

Import Quantity MT	2000-2001	2001-2002	April-Dec.2002
Subject countries	48	1060.6	3412.27
Other countries	3276.31	4486.07	120.7
Total	3324.31	5546.67	3532.34
%age share of subject countries	1.44%	19.12%	96.6%

The Authority finds that there has been significant increase in the dumped imports from subject countries in absolute terms. The imports increased from 48 MT in 2000-01 to 1060.6 MT in 2001-02 and to 3412.27 MT during POI. There was an increase from 1.44% in 2000-01 to 96.6% during the POI. Therefore, there was an increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms.

#### Market share:

40. The Authority finds that the market share of the domestic industry and the imports from the subject countries in the demand of subject goods has been as under :

Quantity (MT)	2000-2001	2001-2002	April-Dec.2002 (POI)	POI Annualised
Imports	3324.31	5546.67	3532.34	4709.79
Domestic Sales	***	***	***	***
Demand	***	***	***	***
Share of domestic industry (%)	68.41	55.20	66.11	66.11
Share of imports from subject countries (%)	0.46	8.57	32.74	32.74

The Authority finds that the share of imports of subject goods from subject countries has increased from 0.46% during 2000-2001 to 32.74% during POI. There is thus an increase in the dumped imports from subject countries in relation to the demand of the product in the country.

#### Production and Capacity Utilisation:

41. The Authority finds that the production and capacity utilization of the domestic industry has been as under :

	2000-2001	2001-2002	POI
Capacity	11250	11250	8438
Production	7316.15	7129.45	6037
Capacity Utilization %	65.03	63.37	71.54

The Authority finds that there has been improvement in the capacity utilization of the domestic industry during the period of investigation in comparison to the earlier years.

#### Sales Volume:

42. Sales volumes of domestic industry increased from \*\* in 2000-01 to \*\*\* in POI and indexed figures are as under :

Year	Sales Volume (MT)	Unit Price Rs./MT
2000-2001	100	100
2001-2002	95	92.53
April- Dec. -2002 (POI-Annualized)	127.6	91.05

The Authority finds that the volume of sales of domestic industry have increased during the POI in comparison to earlier years. However, the unit value realization has gone down significantly.

#### Inventory :

43. The inventory of finished stock has been as under :

2000-2001	2001-2002	POI
100 MT	130.33 MT	26.84 MT

Indexed

The Authority finds that the inventory of finished goods held by the domestic industry has declined considerably at the end of POI in comparison to the previous year closing on March, 2002.

### Price Undercutting

44. The Authority finds that the price undercutting due to the dumped imports has been as under :

	China	SKC Korea	Korea Others	Taiwan	Brazil
Average Net Sales realization of domestic industry	***	***	***	***	***
Landed Value of imports	***	***	***	***	***
Price Undercutting as % of NSR	12.31	8.20	8.59	14.57	23.05

### Employment :

45. There have been a drastic decline in manpower from 576 in 2000-2001 to 430 during the period of investigation.

### Wages :

46. The Authority notes that the domestic industry has not been able to grant any increments or promotions during the last few years. All bonuses other than the statutory bonus have been reduced substantially. The company is not in a position even to conclude a fresh wage settlement with the labour union under Section 12(3) of the Industrial (Disputes & Regulation) Act which has been due since January 2001 despite numerous representations made to the management.

**Profitability:**

47. The domestic industry has suffered direct losses on per unit sale of subject goods as per information below :

Year	Sales Value (Rs./Lakhs)	Cost of Sales (Rs./Lakhs)	Profit/Loss per unit
2000-01	***	***	(-) 3.59%
2001-02	***	***	(-) 9.71%
April-Dec. 2002 (POI)	***	***	(-) 5.37%

The Authority finds that the per unit losses on the sale of subject goods have increased significantly during the POI in comparison to the earlier years. Since the company is suffering losses, the return on investments is negative.

**Evidence of Lost Contracts**

48. The domestic industry has produced some evidence of loss of orders in the form of copies of orders purportedly placed by suppliers from China.

**Actual and potential negative effect on cash flows**

49. The Authority finds that the domestic industry has suffered cash loss during the period of investigation in the sale of subject goods, which has caused strain on the cash flow position of the company as a whole.

**Growth:**

50. The Authority finds that because of losses, it would not be feasible for the domestic industry to make any new investment.

**Conclusions on Injury**

51. After above examination of various economic factors, the Authority has made following conclusions regarding injury :

- (i) There has been significant increase in the volume of dumped imports from subject countries in absolute terms as well as in relation to the demand of the said product in India.
- (ii) The market share of the domestic industry in total demand has declined in comparison to year 2000-01.
- (iii) The domestic industry has suffered injury on account of price undercutting by the dumped imports.
- (iv) As a result of low sales realization, the domestic industry has suffered losses in the sale of subject goods.



- (v) The domestic industry has not been able to retain the existing manpower. They have not been able to negotiate a fresh wage contract with their employees union.
- (vi) Due to financial losses, the domestic industry is not able to make further investments in their business.
- (vii) There has been improvement in the production and capacity utilization of the domestic industry during the POI. The sales volumes have increased. The inventory level has come down.
- (viii) The Authority, however, concludes that despite improvement in production, capacity utilization, sales volumes and reduced inventory, the domestic industry has suffered injury due to significant increase in the volume of imports from subject countries at dumped prices. The dumped imports have led to price undercutting and financial losses.

#### **Cumulative assessment of injury**

52. As per annexure-II (iii), in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%. The Authority has also found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article in the light of conditions of competition between the imported products and the domestically produced goods. The Authority has found that there is a cumulative effect of injury by imports of subject goods from subject countries on the domestic industry.

#### **G. CAUSAL LINK**

53. The Authority has examined the impact of the dumped imports on the domestic industry as per principle (v) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules. The relevant indices as set forth in para (iv) of Annexure II of the Rules have been examined by the Authority.

54. The Authority has considered the views expressed by the petitioners and other interested parties as regards the causal link, which have been mentioned, in the preceding paragraphs. After examining the various

economic parameters as above the Authority has come to the following conclusions :

- i) There has been an increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms.
- ii) The market share of the dumped imports from the subject countries has increased significantly during POI in comparison to the previous years.
- iii) The net sales realization of the domestic industry has been significantly lower than the landed value of imports from subject countries. The net sales realization has been below the non-injurious price (NIP) on account of dumped imports.
- iv) The domestic industry has suffered financial losses due to low price realization in the sale of subject goods.
- v) As a result of lower landed value of imports of subject goods from subject country, the domestic industry has not been able to realize a fair and reasonable price for its products. This has led to negative return on investment.
- vi) The above economic parameters cumulatively and collectively establish that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.
- vii) The demand of the subject goods has not decreased but has instead increased and therefore, contraction of demand cannot be attributed as a cause of injury. No technological development in the industry or any other such factor which could have resulted in injury to the domestic industry has been noticed. The domestic industry has been able to achieve higher capacity utilization during the POI in comparison to the previous years. Therefore, the injury cannot be attributed to low productivity.

#### **H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST**

55. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

56. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the user-industry using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

## I. CONCLUSIONS

57. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Subject goods have been exported to India from subject countries below their normal value;
- (ii) The domestic industry has suffered material injury; and
- (iii) The material injury has been caused cumulatively by the dumped imports from subject countries.

58. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of subject goods from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty not exceeding the margin of dumping or the margin of injury whichever is lesser and which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the non-injurious selling price of the domestic industry determined for the period of investigation.

59. Accordingly, the Authority recommends that provisional anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000 to 4000 falling under Chapter Heading 3907 2000 of Schedule I of Custom Tariff Classification originating in or exported from China PR, Republic of Korea, Taiwan and Brazil pending final determination. The anti dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column 9 in the following table and the landed value of imports of the subject goods in US\$/kg.

S.No	Sub-Heading	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	3907.2000	Flexible Slabstock Polyol	Molecular Weight 3000 to 4000	P.R. China	Any country	Any producer	Any exporter	1463.71	MT	US\$
2.	3907.2000	Flexible Slabstock Polyol	Molecular Weight 3000 to 4000	Any country	P.R. China	Any producer	Any exporter	1463.71	MT	US\$
3.	3907.2000	Flexible Slabstock Polyol	Molecular Weight 3000 to 4000	Republic of Korea	Any country	Any producer	Any exporter	1463.71	MT	US\$
4.	3907.2000	Flexible Slabstock Polyol	Molecular Weight 3000 to 4000	Any country	Republic of Korea	Any producer	Any exporter	1463.71	MT	US\$

5.	3907.2000	Flexible Slabstock Polyol	Molecular Weight 3000 to 4000	Taiwan	Any country	Any producer	Any exporter	1463.71	MT	US\$
5.	3907.2000	Flexible Slabstock Polyol	Molecular Weight 3000 to 4000	Any country	Taiwan	Any producer	Any exporter	1463.71	MT	US\$
7.	3907.2000	Flexible Slabstock Polyol	Molecular Weight 3000 to 4000	Brazil	Any country	Any producer	Any exporter	1463.71	MT	US\$
8.	3907.2000	Flexible Slabstock Polyol	Molecular Weight 3000 to 4000	Any country	Brazil	Any producer	Any exporter	1463.71	MT	US\$

60. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

#### J. FURTHER PROCEDURE

61. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of these preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
- (c) The Authority would provide opportunity to all the interested parties for making oral submissions which have to be rendered thereafter in writing;
- (d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
- (e) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority